LKS
दैनिक लोकतंत्र की शान
लोकतंत्र का स्तंभ
RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928
www.loktantrakishaan.com
दिल्ली से प्रकाशित
शुक्रवार 15 मई 2026

मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर ब्रिक्स देशों की एकजुटता महत्वपूर्णः भारत

ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता हैं ब्रिक्स

एजेंसी। नई दिल्ली

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों से वैश्विक संघर्षों, आर्थिक अस्थिरता और व्यापारिक व्यवधानों से निपटने के लिए "व्यावहारिक तालमेल" विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों की एकजुटता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जयशंकर ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया अभूतपूर्व भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और कोविड महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। इसके अलावा वैश्विक व्यवस्था में शक्ति संतुलन और लोकतांत्रिक पुनर्संतुलन की प्रक्रिया भी जारी है, जिसे सभी देश सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों का असर ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा पर पड़ा है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान,

बढ़ती महंगाई और आर्थिक वृद्धि की सीमित संभावनाओं ने विकासशील देशों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला और विविधीकृत बाजारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वैश्विक संकटों के प्रभाव को कम किया जा सके। केवल चर्चा पर्याप्त नहीं है, बल्कि ब्रिक्स देशों को समन्वित और प्रभावी कदम भी उठाने होंगे। जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा के मुद्दे आज भी वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में हैं। उन्होंने हाल के संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और अधिक रेखांकित किया है। भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है तथा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बुनियाद होना चाहिए। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि गाजा संघर्ष के गंभीर मानवीय परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने स्थायी युद्धविराम, मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में विश्वसनीय प्रयासों की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि भारत फिलिस्तीन मुद्दे पर दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। जयशंकर ने कहा कि लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे समुद्री मार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। उन्होंने लेबनान, सीरिया, सूडान, यमन और लीबिया की परिस्थितियों पर भी चिंता जताते हुए कहा कि इन संकटों के समाधान के लिए निरंतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से गुरुवार को ब्रिक्स देशों तथा अन्य भागीदार देशों के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने मुलाकात की।उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, इथियोपिया के विदेश मंत्री गेदियन तिमोथियोस हेसेबोन और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो सहित अन्य प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 14-15 मई तक जारी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रह्मणयम जयशंकर कर रहे हैं। इस वर्ष का विषय है- लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इसका उद्देश्य भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता तथा इस समूह का रणनीतिक, आर्थिक और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित दृष्टिकोण दर्शाता है। इस दौरान रूस, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और अन्य ब्रिक्स भागीदार देशों के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

केरल के मुख्यमंत्री का चयन 10 दिन में

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे अधिक चर्चा जिस मुद्दे को लेकर हुई, वह केवल जीत-हार तक सीमित नहीं रही, बल्कि कांग्रेस संगठन की कार्यप्रणाली और नेतृत्व क्षमता भी बहस के केंद्र में आ गई। विशेष रूप से केरल में कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) को स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री के चयन में दस दिन का समय लगना राजनीतिक हलकों में चर्चा और आलोचना का विषय बन गया। गौरतलब है कि 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे और कांग्रेस के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या थी। बावजूद इसके पार्टी मुख्यमंत्री के नाम पर जल्दी निर्णय नहीं ले सकी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विधायक दल के नेता के चयन का अधिकार पहले ही दे दिया गया था। उन्होंने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी की, लेकिन आम सहमति नहीं बन सकी। अंततः पार्टी को जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, दीपा दासमुंसी और अजय माखन जैसे वरिष्ठ नेताओं को केरल भेजना पड़ा। दो दिन की मशक्कत के बाद वीडी सतीशन के नाम पर सहमति बनी और उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। यह स्थिति उस पार्टी के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक मानी जाएगी, जो कभी देश की सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति थी। केरल जैसे राज्य, जहां कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सीधा राजनीतिक जुड़ाव रहा है, वहां भी नेतृत्व चयन को लेकर इतना लंबा गतिरोध कांग्रेस की आंतरिक स्थिति को उजागर करता है। विडंबना यह रही कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और यूडीएफ के कई सहयोगी दल पहले ही वीडी सतीशन के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके थे। सतीशन लंबे समय से कांग्रेस संगठन में सक्रिय रहे हैं और उन्हें जमीनी नेता माना जाता है। इसके बावजूद कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन और गुटबाजी इतनी मजबूत रही कि निर्णय लेने में पार्टी नेतृत्व को अत्यधिक समय लग गया।

दरअसल, कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत ही आज उसकी कमजोरी बनती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक माहौल होने के कारण हर नेता अपनी बात खुलकर रखने और अपने हित साधने की कोशिश करता है। यदि उसकी बात नहीं मानी जाती तो कई बार वह पार्टी छोड़कर क्षेत्रीय दल बना लेता है या भाजपा में शामिल हो जाता है। कांग्रेस के केंद्र में सत्ता से बाहर होने के बाद यह प्रवृत्ति और तेज हुई है। आज कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत दिखाई देती है, वहां भी आंतरिक खींचतान उसके लिए चुनौती बनी हुई है। कर्नाटक इसका बड़ा उदाहरण है, जहां सरकार बनने के बाद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर समय-समय पर विवाद सामने आते रहते हैं। कांग्रेस का बड़ा समय विपक्ष से लड़ने के बजाय अपने ही नेताओं के बीच संतुलन बनाने में निकल जाता है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने पिछले एक दशक में अपने संगठन को अधिक केंद्रीकृत और अनुशासित बनाया है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

केरल को मिला नया नेतृत्व, वीडी सतीशन होंगे राज्य के अगले मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। कांग्रेस ने गुरुवार को वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन को केरल का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं मुकुल वासनिक, दीपा दास मुंशी और अजय माकन ने इस फैसले की औपचारिक घोषणा की। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वीडी सतीशन और कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। करीब 10 दिनों तक चली चर्चा और सहयोगी दलों से विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने सतीशन के नाम पर मुहर लगाई। बताया जा रहा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) सहित यूडीएफ के कई सहयोगी दलों ने भी सतीशन के पक्ष में खुलकर समर्थन दिया। वीडी सतीशन को 2026 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी का मुख्य चेहरा माना जा रहा है। उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई। पिछले पांच वर्षों में विपक्ष के नेता के रूप में सतीशन ने विभिन्न जन मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार को घेरने में अहम भूमिका निभाई। कोच्चि के पास एर्नाकुलम जिले के नेट्टूर में 31 मई 1964 को जन्मे वीडी सतीशन का परिवार लंबे समय से कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा रहा है।

मैं अमेरिका के कुछ लोगों की परवाह नहीं करताः ट्रंप

बीजिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दो दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में अमेरिका और चीन के राष्ट्रगान बजाए गए। ट्रंप और शी ने रेड कार्पेट पर चलते हुए सैन्य गार्ड का निरीक्षण किया। समारोह स्थल पर मौजूद दर्जनों बच्चों ने फूलों के साथ नेताओं का अभिवादन किया। बीजिंग में बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए कहा कि चीनी नेता के साथ उनके बेहद शानदार रिश्ते हैं और दोनों देशों के संबंध पहले से भी ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। ट्रंप ने शी को एक महान देश का महान नेता भी बताया और कहा कि अमेरिका में कुछ लोगों की आलोचना के बावजूद वह यह बात खुले तौर पर कहते हैं। यह यात्रा मूल रूप से मार्च में निर्धारित थी, लेकिन ईरान युद्ध के कारण इसमें देरी हुई। गौरतलब है कि ट्रंप आखिरी बार 2017 में राष्ट्रपति के रूप में चीन आए थे, लेकिन इस बार उनका सामना एक अधिक मुखर और शक्तिशाली चीन से है, जो खुद को एक स्थिर वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करने के लिए उत्सुक है। ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ अपनी मुलाकात को अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन बताया। दोनों नेताओं ने अपने-प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू की है। ट्रंप ने शी के साथ अपने निजी तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि उनसे मिलना उनके लिए सम्मान की बात है।

वकील की ड्रेस में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी गुरुवार सुबह वकील की पोशाक पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचीं। जानकारी के मुताबिक, वह विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी एक जनहित याचिका मामले में चीफ जस्टिस सुजॉय पाल की बेंच के समक्ष दलीलें पेश करने पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी अदालत की कार्यवाही के कई पहलुओं पर सवाल उठा सकती हैं। उनके हाई कोर्ट पहुंचने के बाद अदालत परिसर में राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई। लंबे समय बाद किसी बड़े राजनीतिक नेता को स्वयं अदालत में पेश होकर बहस करते देखना चर्चा का विषय बन गया है। यह जनहित याचिका टीएमसी नेता और वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय के बेटे शीर्षान्या बंदोपाध्याय द्वारा दायर की गई थी। मामले में चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा और उससे जुड़े प्रशासनिक कदमों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ममता बनर्जी इससे पहले भी कानूनी मामलों में सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं। हाल ही में वह एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील पक्ष रख चुकी हैं।

ट्रंप चीन तो अरागची दिल्ली में, होर्मुज पर तनाव के बीच गुजरा भारतीय जहाज

एजेंसी। नई दिल्ली

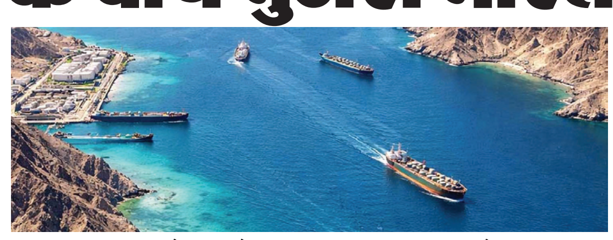

दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों, अमेरिका और चीन ने वैश्विक व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर एक बड़ी सहमति व्यक्त की है। अमेरिकी जानकारी के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत में यह तय हुआ है कि इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी देश को अतिरिक्त शुल्क या टोल लगाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह चर्चा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीजिंग में होने वाली शिखर बैठक से ठीक पहले हुई है, जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। इसी बीच, कूटनीतिक मोर्चे पर एक और बड़ी खबर आई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ युद्ध को विराम देने की दिशा में जारी बातचीत में सकारात्मक प्रगति हो रही है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप चीन की राजकीय यात्रा पर हैं। दूसरी ओर, भारत की राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए ईरानी विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अरागची भी पहुंचे हुए हैं। मध्य-पूर्व की स्थिति पर नजर डालें तो वहां मानवीय और तकनीकी संकट गहराया हुआ है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किए गए हमलों के बाद से ईरान में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह ठप थीं। हालांकि, अब कुछ क्षेत्रों में इसे आंशिक रूप से बहाल किया गया है, लेकिन आम जनता और ऑनलाइन कारोबार से जुड़े लोग अब भी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। कूटनीतिक दांव-पेच के बीच इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों को लेकर भी विरोधाभास सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने यूएई की एक ऐतिहासिक यात्रा का दावा किया, जिसे यूएई के विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया। इस पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि इजरायल के साथ किसी भी तरह का सहयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीबीआई निदेशक सूद का कार्यकाल एक साल और बढ़ा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रवीण सूद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक पद पर एक वर्ष का सेवा विस्तार और दे दिया है। केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने बुधवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी किया। इसके तहत प्रवीण सूद अब 24 मई 2027 तक सीबीआई निदेशक के पद पर बने रहेंगे। सूत्रों के अनुसार, नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर बनी चयन समिति में किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पैनल में शामिल नए अधिकारियों के नामों के साथ जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर सहमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सरकार के सामने मौजूदा निदेशक को सेवा विस्तार देने का विकल्प बचा। बताया जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में सीबीआई प्रमुख के चयन पर विस्तार से चर्चा हुई थी। इस प्रक्रिया में कुल 39 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया, लेकिन किसी एक नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी। सीबीआई के निदेशक पद के लिए गठित चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं।

ईरान ने दोस्ती निभाते हुए भारत को दिया सुरक्षित रास्ते का भरोसा

नई दिल्ली। मध्य-पूर्व (मिडिल-ईस्ट) में गहराते युद्ध के बादलों और तनावपूर्ण कूटनीतिक माहौल के बीच ईरान ने भारत के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को एक नई ऊंचाई दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए साफ कर दिया है कि रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में भारतीय जहाजों को विशेष रियायत और सुरक्षा दी जाएगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और वैश्विक तेल आपूर्ति के इस मुख्य मार्ग पर ईरान अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ईरानी उप विदेश मंत्री ने भारत को 'दोस्त देश' संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तेहरान और नई दिल्ली इस बात पर सहमत हैं कि क्षेत्रीय तनाव के बावजूद भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिलना चाहिए। गरीबाबादी के मुताबिक, अब तक 11 भारतीय जहाजों को होर्मुज से गुजरने की विशेष अनुमति दी जा चुकी है और 13 अन्य जहाजों की मंजूरी पर काम चल रहा है।

डिजिटल पेंशन सुधारों ने पेंशन वितरण को बनाया सुगम और पारदर्शीः डॉ. जितेन्द्र सिंह

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले दशक में देश के पेंशन प्रशासन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। अब यह प्रक्रियाबद्ध प्रणाली से विकसित होकर प्रौद्योगिकी-सक्षम, जन-केंद्रित तंत्र बन गया है, जो पेंशनभोगियों की गरिमा, पारदर्शिता और जीवन सुगमता पर केंद्रित है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विज्ञान भवन में आयोजित 16वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत को संबोधित करते हुए कहा कि पेंशनभोगियों को सरकारी सहायता लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य योगदानकर्ताओं के रूप में देखना चाहिए, जिनका अनुभव,

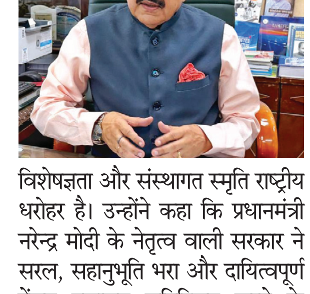

विशेषज्ञता और संस्थागत स्मृति राष्ट्रीय धरोहर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सरल, सहानुभूति भरा और दायित्वपूर्ण पेंशन प्रशासन सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास किए हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि पेंशन अदालत व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी हितधारक साझा मंच पर बैठकर प्रायः मौके पर ही विवाद का सामूहिक समाधान करते हैं, बजाय इसके कि बातचीत केवल नियमित फाइल हस्तांतरण और आधिकारिक पत्राचार तक सीमित रहे। वर्ष 2014 से पेंशन सुधारों का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समय ऐसा था जब पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग लोगों की ध्यान से काफी हद तक बाहर रहते हुए सीमित प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत संचालित होता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में निरंतर सुधारों, डिजिटल उपायों और नागरिक-केंद्रित निर्णय द्वारा यह सरकार के सबसे सक्रिय विभागों में से एक बन गया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और डिजिटल तकनीक द्वारा जीवन प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल बनाने की सरकार की पहल का उल्लेख किया।

ओम बिरला, अमित शाह व अन्य ने छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया

एजेंसी। नई दिल्ली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह सहित कई प्रमुख नेताओं ने गुरुवार को छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर एक्स के माध्यम से उन्हें नमन किया। बिरला ने लिखा, '' छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन ! विपरीत परिस्थितियों में भी स्वराज, संस्कृति और राष्ट्रधर्म की रक्षा के लिए छत्रपति ने जिस अद्वितीय पराक्रम और दृढ़ता का परिचय दिया। वह भारतीय इतिहास में अमर है। उन्होंने अन्याय और आक्रांताओं के सामने कभी समझौता नहीं किया तथा असहनीय यातनाएं सहकर भी अपने सिद्धांतों और विचारों के प्रति अटल रहे। संभाजी महाराज का बलिदान और उनका गौरवशाली जीवन युगों-युगों तक राष्ट्रप्रेम और

साहस की प्रेरणा देता रहेगा। अमित शाह ने लिखा, ''बाल्यकाल से ही राष्ट्रप्रेम, धर्मरक्षा और हिन्दवी स्वराज के संस्कारों को आत्मसात करने वाले छत्रपति संभाजी महाराज जी ने अनेक रणनीतिक क्षेत्रों को मुगलों के कब्जे से मुक्त कराया तथा अनगिनत युद्धों में मुगल सेना को परास्त किया। धर्मांतरण को रोकने के लिए आजीवन कटिबद्ध छत्रपति संभाजी महाराज जी ने स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज की मशाल कभी बुझने नहीं दी और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्गमंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, '' वीरता और पराक्रम के प्रतीक स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को उनकी जयंती (तिथि के अनुसार) पर कोटि-कोटि नमन।

कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि छत्रपति स्वधर्म और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान मराठा योद्धा थे। संसदीय एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के 'हिंदवी स्वराज' के संकल्प को आगे बढ़ाने तथा मराठा साम्राज्य और धर्म की रक्षा हेतु उनका अदम्य साहस, त्याग और बलिदान भारतीय इतिहास की अमर प्रेरणा है।

भारत ने ओमान में भारतीय जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की

नई दिल्ली। ओमान के तट बुधवार को भारतीय झंडे वाले जहाज पर हुए हमले की भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी कर रहा कि ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा, " हमला अस्वीकार्य है और हम इस बात की निंदा करते हैं कि कमर्शियल जहाजों और आम नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहाज पर सवार सभी भारतीय क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। भारत ने बचाव अभियान के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने, निर्दोष आम क्रू सदस्यों की जान जोखिम में डालने या किसी भी तरह से जहाजों के आने-जाने और व्यापार की आजादी में रुकावट डालने से बचा जाना चाहिए।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEU-TICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

खास खबर

शिवराज चौहान की पुस्तक 'अपनापन' का 26 मई को लोकार्पण

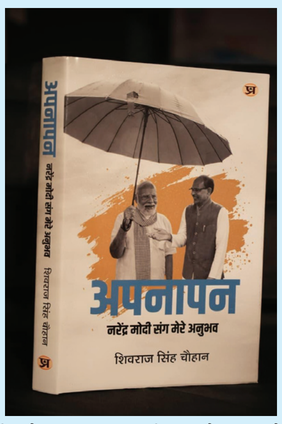

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ 35 वर्षों के अनुभवों पर पुस्तक 'अपनापन' लिखी है। पूर्व उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा 26 मई को पूसा में पुस्तक का विमोचन करेंगे। शिवराज सिंह ने गुरुवार को अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में अपनी पुस्तक 'अपनापन' की बात करते हुए कहा कि यह पुस्तक पाठकों को प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व, नेतृत्व, संवेदनशीलता और कार्यशैली को अधिक आत्मीयता से समझने का अवसर देगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका 35 वर्षों से भी अधिक पुराना साथ है। साल 1991 की एकता यात्रा से शुरू हुआ यह संबंध संगठनात्मक कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ हुआ और आगे चलकर मुख्यमंत्री, फिर केंद्रीय मंत्री के रूप में भी विभिन्न जिम्मेदारियों में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। शिवराज ने कहा कि दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को एक निर्णायक और प्रभावशाली नेता के रूप में देखती है लेकिन उन्होंने उनमें एक साधक, कर्मयोगी और राष्ट्रहित के लिए पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व को बहुत निकट से देखा है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी देर रात तक काम करने के बाद भी अगले दिन उसी ऊर्जा, उसी स्पष्टता और उसी प्रतिबद्धता के साथ देश के लिए खड़े दिखाई देते हैं। शिवराज सिंह ने स्पष्ट किया कि 'अपनापन' केवल घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि एक विचार, एक दृष्टि, एक कार्यपद्धति और राष्ट्र निर्माण की उस भावना का दस्तावेज है, जिसने भारत को बदलने का साहस दिखाया। इस पुस्तक में पाठकों को संगठन से सरकार तक, संवेदना से निर्णय तक और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा की निकटतम झलक मिलेगी।

वीडी सतीसन होंगे केरल के नए मुख्यमंत्री, दिल्ली में कांग्रेस की आधिकारिक घोषणा

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को वीडी सतीशन को केरल का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की।दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, दीपा दासमुंशी, अजय माकन और राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक की मौजूदगी में केरल के नये मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की गई। इससे पहले 7 मई को तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केरल के लिए नए नेता के चयन का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा गया था। इसे लेकर चली लंबी चर्चा के बाद आखिरकार पार्टी की तरफ से केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के नेतृत्व के लिए वीडी सतीसन के नाम पर अंतिम निर्णय लिया गया है।

बियोंड साइलेंस-सांझबाती और स्वरछंद द्वारा प्रस्तुत एक यादगार शाम

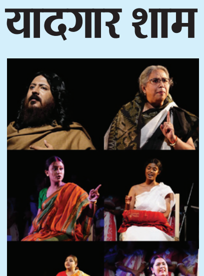

लोकतंत्र की शान : रवींद्रनाथ टैगोर की 165 वीं जयंती के अवसर पर, 'सांझबाती फाउंडेशन' और 'स्वरछंद' ने संयुक्त रूप से दिल्ली के मंडी हाउस स्थित एलटीजी सभागार में 'बियोंड साइलेंस– टैगोर्स विमेन' का मंचन किया। स्वरछंद ने बंगाली में रवींद्र संगीत प्रस्तुत किया, जबकि सांझबाती ने हिंदी में नाटक प्रस्तुत किया। शुद्धा बैनर्जी और नंदिनी बैनर्जी द्वारा परिकल्पित इस प्रस्तुति में, नील बैनर्जी को रवींद्रनाथ टैगोर की आवाज़ के रूप में देखा गया, जो उन्हें उनके लिखे हुए महिला पात्रों की आंतरिक दुनिया की ओर मार्गदर्शन करते हैं। सौदामिनी, गिरिबाला, मंजुलिका, गोरा कहानी से आनंदमयी और देना पाओना से निरुपमा—ये सभी समाज के भेदभाव, कट्टरता और परंपराओं के खिलाफ चुप्पी से ही सही लेकिन शक्तिशाली विरोध का प्रतीक बन गईं। कृतिका भाटिया, अरण्य सिंघा, नैसर्गिका दास हलदर, संगीता सान्याल और तस्मिया तान्हा के प्रदर्शन ने मंच को और भी प्रभावशाली और जीवंत बना दिया। बंगाली भाषा की सीमा को पार करके व्यापक दर्शकों तक पहुंचने की यह पहल निस्संदेह प्रशंसा के योग्य है।

ममता बनर्जी के वकील के लिबास में कोर्ट पहुंचने पर बीसीआई ने मांगी एनरॉलमेंट की जानकारी

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील के लिबास में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पेश होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से उनके एनरॉलमेंट की जानकारी मांगी है। बीसीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीमांतो सेन ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के सेक्रेटरी को गुरुवार को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है। बीसीआई ने राज्य बार काउंसिल से ममता बनर्जी के बतौर वकील एनरॉलमेंट को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। बीसीआई ने पत्र में कहा है कि उन्हें विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स से ये जानकारी मिली है कि आज ममता बनर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील के लिबास और गले में व्हाइट बैंड लगाकर पेश हुईं। पत्र में कहा गया है कि वकीलों के प्रोफेशनल व्यवहार बीसीआई के रूल्स के निर्देशित होते हैं। बीसीआई रुल्स के चौथे और छठे खंड में वकीलों को विभिन्न कोर्ट में पेश होने के लिए ड्रेस कोड का जिक्र किया गया है। पत्र में कहा गया है कि ममता बनर्जी साल 2011 से लेकर 2026 तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ममता बनर्जी के संवैधानिक और सार्वजनिक पद पर रहने और वकील के रुप में अचानक पेश होने के बाद बीसीआई उनके एनरॉलमेंट के स्टेटस की जानकारी चाहता है। बीसीआई ने ममता बनर्जी का एनरॉलमेंट नंबर, एनरॉलमेंट की तिथि और क्या उनका एनरॉलमेंट अभी भी जारी है, इसकी जानकारी मांगी है। बीसीआई ने एनरॉलमेंट होने की स्थिति में उससे संबंधित शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध कराने को कहा है।

रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, यूक्रेन और पश्चिम एशिया पर चर्चा

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और भारत-रूस द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति सहित विभिन्न क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी को दिसंबर 2025 में आयोजित 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की बैठक के बाद से द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी।बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम समेत आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान एक बार फिर भारत के उस स्थायी रुख को दोहराया कि किसी भी विवाद के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही सबसे बेहतर मार्ग है। प्रधानमंत्री ने रूसी विदेश मंत्री से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं पहुंचाने का भी अनुरोध किया।

बस्तर विकास मॉडल पर दिल्ली में मंथन, अमित शाह से विष्णु देव साय की अहम मुलाकात

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बस्तर में तेजी से बदल रहे हालात और विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में विशेष रूप से बस्तर में चल रहे 'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया को बताया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को दूरस्थ्य गांव में पहुंचाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं से अवगत कराया। जिन इलाकों में कभी एम्बुलेंस पहुंचना मुश्किल माना जाता था, वहां अब डॉक्टर, दवाइयां और स्वास्थ्य टीमें नियमित रूप से पहुंच रही हैं। दूरस्थ गांवों में पैदल जाकर लोगों की जांच की जा रही है और गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान कर निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मात्र एक महीने में 21.86 लाख से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच हो चुकी है और उनके डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार कर लिए गए हैं। हजारों मरीजों को समय पर उपचार और उच्च अस्पतालों में रेफर किया गया है। उन्होंने कहा कि बस्तर में पुराने सुरक्षा शिविर केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गए हैं, इन्हें धीरे-धीरे जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां गांव के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जरूरी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं। इन केंद्रों के जरिए दूरस्थ और नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को पहली बार कई बुनियादी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। ग्रामीण अब इलाज, बैंक खाते, दस्तावेज और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए दूर-दूर तक भटकने को मजबूर नहीं हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान जो 13 अप्रैल 2026 को सुकमा से शुरू हुआ, इस अभियान में 36 लाख लोगों को लक्षित किया गया है। इसके अलावा बस्तर मुन्ने (अग्रणी बस्तर) अभियान के जरिए 31 महत्वपूर्ण योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। जगदलपुर में नया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू हो गया है, जहां अब बस्तर के लोग महंगे इलाज के लिए रायपुर या बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा। डायल-112 की नेक्स्ट जेन सेवा का विस्तार और पुराने सुरक्षा शिविरों को "जन सुविधा केंद्र" में बदलने की योजना भी बस्तर के स्थायी विकास की दिशा में अहम कदम हैं। उन्होंने बताया कि जो इलाके कभी नक्सल प्रभाव के कारण मुख्यधारा से कटे हुए थे, वहां आज सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। हाल ही में सुकमा के एक अत्यंत दुर्गम गांव से गंभीर मरीज को सैकड़ों किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचा कर उपचार दिलाना इस बदलाव का बड़ा उदाहरण बना है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को बस्तर के लिए तैयार विकास रोडमैप की भी जानकारी दी। इसमें सड़क, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन से बस्तर में तेजी से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में हो रहे विकास कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उल्लेखनीय है कि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 18 और 19 मई को बस्तर प्रवास भी संभावित है।

शिवराज चौहान करेंगे 5 लाख पीएमएवाई-जी आवासों के गृह प्रवेश का शुभारंभ

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 मई को महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल ग्राउंड में आयोजित "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लाभार्थी सम्मेलन एवं महा आवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह" में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत पूर्ण हुए 5 लाख आवासों के गृह प्रवेश का शुभारंभ करेंगे। साथ ही, 6 पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को आवास की चाबियां भी सौंपेंगे, जिनमें योजना के अंतर्गत 3 करोड़वें आवास से जुड़े लाभार्थी भी शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 हेतु 8,368.50 करोड़ रुपये की केंद्रीय अंश की मातृ स्वीकृति जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-IV के अंतर्गत 122.98 करोड़ रुपये की लागत से 35 सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति भी जारी करेंगे, जिससे राज्य की 35 ग्रामीण बसावटें लाभान्वित होंगी। कार्यक्रम के दौरान 'महा आवास अभियान 2023-24' के अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में 'महा आवास अभियान अवॉर्ड्स गौरवगाथा पुस्तिका' एवं त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाएगा।

दिल्ली के सरकारी कर्मचारी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम, सरकार छह महीने तक नहीं खरीदेगी कोई वाहन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के कार्यालयों में सप्ताह में दो दिनों वर्क फ्रॉम होम और सरकारी वाहनों के ईंधन की खपत 20 फीसदी कम करने जैसी कई घोषणाएं कीं। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद लिया गया है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसले लिए गए।मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस कांफ्रेंस करते बताया कि वैश्विक अनिश्चितता के समय हर नागरिक अपनी जीवनशैली में छोटे बदलाव करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। दिल्ली सरकार इस अपील को 90 दिनों के जन-अभियान में बदलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। इसके साथ-साथ निजी सेक्टर को भी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का परामर्श जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी वाहनों में ईंधन की खपत को 20 फीसदी कम किया जाएगा। हर सोमवार सभी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी मेट्रो से दफ्तर आएगे। उन्होंने नागरिकों से सप्ताह एक दिन निजी वाहनों का उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार में नए पेट्रोल/ डीजल/ सीएजी/ हाईवर्ड गाड़ियों की अगले 6 महीने तक कोई खरीद नहीं होगी। कर्मचारी के ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10 प्रतिशत से बढाकर 20 फीसदी दिया जाएगा, यदि कर्मचारी अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 20 फीसदी मेट्रो/ डीटीसी/पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड के लिए उपयोग करता है। माल ढुलाई के लिए ट्रक के स्थान पर ट्रेन का उपयोग करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी अगले एक साल तक किसी सरकारी विदेश यात्रा पर नहीं जाएंगे। दिल्ली सरकार 100 फीसदी भारत में बने प्रोडक्ट्स का उपयोग करने को प्राथमिकता देगी।

सबरीमाला मामले पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की नौ जजों की संविधान बेंच ने सबरीमाला मंदिर मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर 16 दिनों तक सुनवाई की। उच्चतम न्यायालय की 9 जजों की संविधान बेंच ने इस मामले पर 7 अप्रैल से सुनवाई शुरु की थी। केंद्र सरकार ने इस मामले पर दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि सबरीमाला मंदिर में माहवारी से जुड़े आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर रोक धार्मिक आस्था और स्वायतता का मामला है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से इस प्रतिबंध को बरकरार रखने की मांग की है और कहा है कि ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमा सीमित होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एजे मसीह, जस्टिस पीबी वराले, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल हैं। 28 सितंबर 2018 को उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के साथ काफी समय से भेदभाव होता रहा है। महिला पुरुष से कमतर नहीं है। एक तरफ हम महिलाओं को देवी स्वरुप मानते हैं दूसरी तरफ हम उनसे भेदभाव करते हैं। कोर्ट ने कहा था कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल वजहों से महिलाओं के धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता को खत्म नहीं किया जा सकता है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा समेत चार जजों ने कहा था कि ये संविधान की धारा 25 के तहत मिले अधिकारों के विरुद्ध है। जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने बाकी चार जजों के फैसले से अलग फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि धार्मिक आस्था के मामले में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पूजा में कोर्ट का दखल ठीक नहीं है। मंदिर ही यह तय करे कि पूजा का तरीका क्या होगा।

चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अधिकारी 19 मई को कोर्ट में तलब

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने चंबल अभयारण्य में अवैध खनन जारी रहने पर राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य के कई अफसरों को 19 मई को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (गृह), खनन, वित्त, वन, पर्यावरण, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभागों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो निजी तौर पर हलफनामा दाखिल कर बताएं कि कोर्ट के पहले के आदेश के पालन के लिए उन्होंने क्या किया।उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर चिंता जताई कि खनन क्षेत्र में ट्रैक्टर्स और वाहनों की निर्बाध आवाजाही की पहचान नहीं की जा रही है। कोर्ट ने अवैध खनन का परिवहन रोकने के लिए उठाये गए कदमों की विस्तृत जानकारी भी मांगी है। इसके पहले 17 अप्रैल को चंबल अभ्यारण्य में अवैध खनन पर सख्त रवैया अपनाते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को हाई रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने और जीपीएस ट्रैकिंग करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि अगर अवैध खनन का कोई मामला सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे तुरंत कार्रवाई करें और मौके पर टीम भेजें और कठोर कदम उठाएं। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि अवैध खनन से प्रभावित इलाकों में ऊंचे खंभों पर हाई रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उनकी लाइव फीड संबंधित जिले के एसपी या एसएसपी और संबंधित वन अधिकारी की सीधी निगरानी में रहे। कोर्ट ने आदेशों के उल्लंघन को अवमानना मानते हुए अफसरों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उच्चतम न्यायालय ने इन राज्यों से आदेश के अनुपालना संबंधी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि खनन गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों जैसे ट्रैक्टर, अर्थ मूवर्स और लोडर्स आदि में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएं। इससे इन वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। कोर्ट ने साफ कहा था कि जो भी वाहन चंबल इलाके से गुजरे उसमें ट्रैकर लगा होना चाहिए ताकि अवैध रेत परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।इसके पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मध्यप्रदेश के मुरैना में एक फॉरेस्ट गार्ड पर रेत माफिया द्वारा ट्रैक्टर ट्राली चढ़ा देने के मामले पर कड़ा एतराज जताया था। कोर्ट ने मध्यप्रदेश के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि जब राज्य की मशीनरी अपने अधिकारियों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में नाकाम है तो उसका क्या अस्तित्व है। अधिकारियों की नाक के नीचे अवैध खनन हो रहे हैं।दो अप्रैल को कोर्ट ने चंबल नदी में अवैध खनन से वन्यजीवों को हो रहे नुकसान पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि खनन माफिया चंबल के नये डकैत हैं। कोर्ट ने कहा था कि राजस्थान में खनन माफिया पुलिस, वन और प्रशासनिक अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी, जिसमें चंबल अभयारण्य की 732 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित क्षेत्र से बाहर करने की कोशिश की गई थी।

जंतर-मंतर रोड बंगला की रजिस्ट्री कराने मांग पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जंतर-मंतर रोड के एक बंगले की रजिस्ट्री कराने की कांग्रेस पार्टी की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की याचिका के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे अंतरिम सुरक्षा की मांग पर तभी विचार करेंगे जब वो इस सवाल पर संतुष्ट हो जाएगा कि याचिका सुनवाई के योग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी याचिका में कहा है कि 7, जंतर-मंतर रोड का बंगला उसे 16 जनवरी 1956 में ही आवंटित किया गया था। इसके लिए पार्टी ने 1959 में ही पूरा पैसा जमा कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने 21 मई 1959 को इसके लिए 6,10,700 रुपयों के अलावा अतिरिक्त प्रीमियम और वार्षिक किराया भी जमा किया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को उस बंगले पर कब्जा करने के लिए कहा गया। कांग्रेस पार्टी ने याचिका में आरटीआई से मिली सूचना का जिक्र किया है जिसमें दिल्ली सरकार के लैंड एंड बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों ने इस बंगले का रजिस्ट्री कराने को कहा था। याचिका में कांग्रेस पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के 2014 के जनता दल बनाम कांग्रेस और अन्य के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि 1969 के पहले की कांग्रेस पार्टी के पास जो भी संपत्ति थी वो वर्तमान कांग्रेस पार्टी की होगी। याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी 2017 से प्रशासन को लगातार इस बात का प्रतिवेदन दे रही है कि इस बंगले की रजिस्ट्री करायी जाए, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं किया गया, जिसके बाद पार्टी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

संजय कपूर संपत्ति विवादः सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड मीटिंग के एजेंडा पर रोक लगाई

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति विवाद पर सुनवाई करते हुए 18 मई को होने वाली बोर्ड मीटिंग में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और बैंक के कामकाज के लिए अधिकृत व्यक्तियों में बदलाव करने संबंधी एजेंडा पर रोक लगाने का आदेश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश संजय कपूर की मां रानी कपूर की अर्जी पर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जब तक मध्यस्थता चल रही है तब तक सभी पक्षकार किसी विवाद को बढ़ावा नहीं दें। रानी कपूर ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल कर इस मामले की मध्यस्थता प्रक्रिया होने तक प्रिया कपूर और दूसरे लोगों को आरके फैमिली ट्रस्ट के कामकाज में दखल देने से रोकने की मांग की थी। रानी कपूर ने अपनी नई अर्जी में आरके फैमिली ट्रस्ट की 18 मई को होने वाली बोर्ड मीटिंग पर भी रोक लगाने की मांग की थी। ये मीटिंग रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नोटिस पर बुलाई गई थी, जिसका विवादित संपत्ति के एक बड़े हिस्से पर कब्जा बताया जाता है। रानी कपूर की अर्जी में कहा गया था कि इस मीटिंग का मुख्य मकसद बोर्ड में अपनी पसंद के नये डायरेक्टर को नियुक्त करना है। उच्चतम न्यायालय 7 मई को रानी कपूर और प्रिया कपूर के बीच सोना ग्रुप पारिवारिक ट्रस्ट को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने पारिवारिक ट्रस्ट आरके फैमिली ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। रानी कपूर ने अपनी याचिका में कहा है कि आरके फैमिली ट्रस्ट के गठन और उसके प्रबंधन की परिस्थितियां सवालों के घेरे में हैं।याचिका में कहा गया है कि आरके फैमिली ट्रस्ट का गठन बिना याचिकाकर्ता की जानकारी या सहमति के किया गया। इसी वजह से याचिकाकर्ता को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया। ट्रस्ट की सारी संपत्ति उनकी थी लेकिन ट्रस्ट का गठन करते समय उन्हें सूचना तक नहीं दी गई। ट्रस्ट के गठन के समय उन्हें हार्ट का स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब थी। रानी कपूर ने कहा है कि ट्रस्ट के कागजात पर हस्ताक्षर बिना उसका कंटेंट जाने करा लिया गया। कुछ सादे कागजों पर उनके हस्ताक्षर ले लिए गए।

दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुई। इस मौके पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे।उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित तीव्र परिवर्तन के इस युग में शिक्षा राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव बनी रहेगी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिकल्पना की है। उन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा, अकादमिक उत्कृष्टता और आलोचनात्मक चिंतन के मूल्यों पर आधारित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के माध्यम से विश्वविद्यालय एक पसंदीदा संस्थान के रूप में उभर रहा है। उन्होंने स्नातक विद्यार्थियों को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित न रहकर निरंतर सीखने, नवाचार और नेतृत्व को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उपराज्यपाल ने विद्यार्थियों से विकसित भारत और विकसित दिल्ली की निर्माण में सार्थक योगदान देने का आग्रह किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाए दी। उन्होंने कहा कि यह दिन वर्षों की मेहनत, अनुशासन, संघर्ष और सपनों के साकार होने का प्रतीक है। हर विद्यार्थी की यह उपलब्धि उसके परिवार, शिक्षकों और समाज के विश्वास और सहयोग से भी जुड़ी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास, नवाचार और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, रिसर्च, स्टार्टअप, तकनीक और सामाजिक चेतना से जुड़े यही युवा विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं, जो केवल अपने भविष्य ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य को भी नई दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं।

संक्षिप्त समाचार

बृहस्पतिवार को अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा जनपद रामपुर की एक अति आवश्यक बैठक की गई

लोकतंत्र की शान : मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पंडित संदीप शर्मा जिला उपाध्यक्ष के निवास स्थान नूर महल आवास विकास पर आहूत की गई जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज के ऊपर की गई अनुचित एवं आपत्तिजनक टिप्पणी पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया बैठक में पंडित शिवम शर्मा(नगर कोषाध्यक्ष) ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए राजकुमार भाटी जैसे लोग ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हैं जबकि ब्राह्मण समाज ने समाज को जोड़ने का काम किया है बैठक में पंडित गोपाल शर्मा (नगर महामंत्री) ने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियां सामाजिक सुधार एवं समरसता को आहत करने वाली हैं बैठक में पंडित मानस पाठक ने समाजवादी पार्टी की स्थापना एवं उसके विकास कार्यों में स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र, रमाशंकर कौशिक जैसे ब्राह्मण नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान याद दिलाया तथा वर्तमान में भी अनेक ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं बैठक में पंडित तंजुल शर्मा (जिला संगठन मंत्री युवा प्रकोष्ठ) ने कहा राजकुमार भाटी जैसे ब्राह्मण विरोधी को तत्काल पार्टी से बाहर करें। बैठक में बहुत ही जल्दी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन डी एम महोदय के माध्यम से देने का निर्णय लिया गया उचित कार्यवाही नहीं होने पर ब्राह्मण समाज एक उग्र आंदोलन करने पर बाधित होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी बैठक में अभिषेक शर्मा , यश शर्मा, अवनीत शर्मा,रविंद्र शर्मा, लव शर्मा, कुश शर्मा, मुकेश पाठक, विकास पांडे ,दीपक शर्मा, गौरव पाठक, पवन पाठक, प्रदीप श्रोत्रिय, विकास शर्मा ,सुबोध राजन त्रिपाठी, सात्विक भारद्वाज ,मयंक शर्मा, रोहित शर्मा, रामवीर शर्मा, रोहित कुकरेती आदि उपस्थित रहे

रामपुर में आंधी-तूफान का कहर, स्कूटी शोरूम में भारी नुकसान, 15-20 स्कूटियां क्षतिग्रस्त

लोकतंत्र की शान , मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर। उत्तर प्रदेश/जिले में बुधवार देर शाम आए तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचा दी। शहर के सूरज टॉकीज रोड स्थित डीकेएस एंटरप्राइजेज (नूर महल आवास विकास), नियर जीवन हॉस्पिटल के पास बने एक स्कूटी शोरूम में आंधी-तूफान के कारण भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि तूफान इतना तेज था कि शोरूम की दीवार बिल्डिंग से टकराकर टूट गई, जिससे शोरूम में खड़ी स्कूटियां चपेट में आ गईं। इस हादसे में करीब 15 से 20 स्कूटियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। कई स्कूटियों के बॉडी पार्ट्स टूट गए, जबकि कुछ स्कूटियां बुरी तरह दब गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आंधी के दौरान शोरूम के आसपास अफरा-तफरी मच गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। शोरूम में हुए नुकसान को देखकर स्कूटी शोरूम के स्वामी राघव अग्रवाल सदमे में हैं। बताया गया कि नुकसान इतना बड़ा है कि शोरूम मालिक की हालत खराब है और वह मानसिक रूप से परेशान नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह तूफान अचानक आया और कुछ ही मिनटों में भारी तबाही कर गया। शोरूम में हुए नुकसान का अनुमान लाखों रुपये में बताया जा रहा है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और शोरूम में टूट-फूट के बाद सफाई व मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है।

अनुष्का श्रीवास्तव ने सीबीएसई 12वीं में लहराया परचम

लोकतंत्र की शान ,बांदा। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही बांदा जनपद में हर्ष की लहर दौड़ गई है। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक परिवार की सुपुत्री अनुष्का श्रीवास्तव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल अपने विद्यालय, बल्कि पूरे जनपद का मान बढ़ाया है।सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अनुष्का श्रीवास्तव ने 12वीं की परीक्षा में 94.08 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर अनुष्का ने बायो ग्रुप में स्कूल में प्रथम स्थान तथा ओवरऑल स्कूल में दूसरा स्थान हासिल किया है।प्रतिष्ठित परिवार की मेधावी सुपुत्री अनुष्का बांदा के प्रसिद्ध वरिष्ठ सर्जन डॉ. अनुराग श्रीवास्तव (अनुराग नर्सिंग होम) एवं डॉ. अर्चना श्रीवास्तव की सुपुत्री हैं। उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर उनके नाना दिनेश चंद्र खरे (पूर्व ओएसडी, जिलाधिकारी बांदा) और मामा डॉ. प्रसून श्रीवास्तव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया है।अनुष्का की सफलता पर परिवार और शुभचिंतकों का कहना है कि उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन और पढ़ाई के प्रति समर्पण ने आज यह मुकाम हासिल कराया है। अनुष्का की इस उपलब्धि ने सिद्ध कर दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास ईमानदारी से किए जाएं, तो सफलता अवश्य मिलती है।

अधिवक्ता पर हमले के विरोध में वकीलों ने कोतवाली में किया प्रदर्शन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल
जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः गुरुवार को क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब दिनदहाड़े एक अधिवक्ता पर रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर जानलेवा हमला किया गया। घटना के बाद से स्थानीय बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और साथी वकीलों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना रहरा के गांव जयतौली निवासी सरफराज अली पुत्र गफूर खान तहसील में अधिवक्ता है। गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे अपनी पत्नी के साथ रजिस्ट्री दफ्तर से काम निपटाकर दवा लेने जा रहे थे। तहसील परिसर के पास ही पीछे से आई एक स्कूटी ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। जब अधिवक्ता ने इसका विरोध किया, तो स्कूटी सवार हमलावरों ने उन पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित अधिवक्ता भारी संख्या में अधिवक्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचे, तथा कोतवाल राजेश कुमार तिवारी को दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनके साथ मारपीट करने के साथ-साथ उनकी जेब से करीब 7500 रुपये जबरन निकाल लिए। बीच-बचाव करने आईं अधिवक्ता की पत्नी के साथ भी अभद्रता की गई। मौके पर मौजूद भीड़ को इकट्ठा होते देख हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इस दुस्साहसिक घटना की सूचना मिलते ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह और महासचिव ब्रज किशोर के नेतृत्व में भारी संख्या में अधिवक्ता कोतवाली पहुंच गए। अधिवक्ताओं ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि अधिवक्ता की तहरीर मिली है। तत्काल जांच के लिए एसएसआई अमित कुमार को घटनास्थल पर भेजा गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही ह। इस दौरान मंगल सेन शर्मा, वीर सिंह, शेर सिंह बढ़ाना, सुरेश चंद सैनी, विजय पाल सिंह,अनूप सिंह और संजय सिंह, दीनदयाल यादव एडवोकेट समेत दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे।

सम्भल में विकास कार्यों को मिली रफ्तार, वार्ड नंबर 10 सराय तरीन में सड़क निर्माण का निरीक्षण

लोकतंत्र की शान,सैय्यद कुमैल ज़ैदी

सम्भल। नगर पालिका परिषद सम्भल की अध्यक्ष आसिया मुशीर अली खान के नेतृत्व में शहर में विकास कार्य लगातार गति पकड़ रहे हैं। इसी क्रम में अध्यक्ष पति चौधरी मुशीर अली खान ने वार्ड नंबर 10 सराय तरीन पहुंचकर चल रहे सड़क निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित कर्मचारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान चौधरी मुशीर अली खान ने कहा कि नगर पालिका परिषद सम्भल की प्राथमिकता शहर के प्रत्येक वार्ड में बेहतर सड़क, साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से कराया जा रहा है और विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान अधिशासी अधिकारी मणि भूषण तिवारी की कार्यशैली की भी स्थानीय लोगों ने सराहना की। नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर में कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर आम जनता में संतोष दिखाई दे रहा है। मौके पर शमीम वारसी, वसीम कुरैशी सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्थानीय नागरिकों ने सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी जताते हुए नगर पालिका परिषद सम्भल का आभार व्यक्त किया। नगर पालिका परिषद सम्भल द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे सम्भल शहर को आधुनिक और स्वच्छ बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।

जनसेवा के तीन वर्ष पूर्ण होने पर चेयरमैन कौसर अब्बास का सम्मान, कॉलेज की जर्जर छतों का भी किया निरीक्षण

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल/सिरसी। नगर पंचायत सिरसी के चेयरमैन कौसर अब्बास के जनसेवा के तीन वर्ष पूर्ण होने पर जवाहर लाल मेमोरियल नगर पंचायत इण्टर कॉलेज, सिरसी के समस्त स्टाफ द्वारा उनका शाल ओढ़ाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। गौरतलब है कि नगर पंचायत सिरसी का जो भी चेयरमैन होता है, वह जवाहर लाल मेमोरियल नगर पंचायत इण्टर कॉलेज का प्रबंधक भी होता है। इस अवसर पर चेयरमैन कौसर अब्बास ने नगर पंचायत सिरसी की सम्मानित जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के विश्वास, प्यार और समर्थन के बल पर उन्हें लगातार सेवा करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए और अधिक मेहनत, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा है। वहीं, छात्रों की शिकायत पर चेयरमैन कौसर अब्बास ने कॉलेज भवन की छतों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान कुछ छतें जर्जर अवस्था में पाई गईं, जिस पर उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए शीघ्र मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिए। चेयरमैन कौसर अब्बास ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और इंशाअल्लाह जल्द ही आवश्यक कार्य पूर्ण कराए जाएंगे, ताकि छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

56 लाख की लाइटें एक साल में ही हटने लगीं: विकास की जल्दबाजी या सरकारी धन की बर्बादी?

» सड़क चौड़ीकरण ने उठाए सवाल, विभागों में तालमेल की कमी पर जनता नाराज

लोकतंत्र की शान

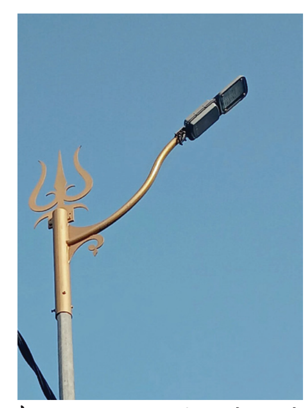

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) बरेली शहर में विकास कार्यों की प्लानिंग और विभागीय समन्वय पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले वर्ष करीब 56 लाख रुपये की लागत से लगाई गई डिजाइनर लाइटों और आकर्षक पोलों को अब सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाया जा रहा है। महज एक साल पहले लगाए गए इन पोलों को उखाड़े जाने से लोगों में नाराजगी है और सरकारी धन की बर्बादी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। शहर के लोग पूछ रहे हैं कि जब सड़क चौड़ीकरण की योजना पहले से प्रस्तावित थी, तो आखिर लाखों रुपये खर्च कर इन लाइटों और सजावटी ढांचे को लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। मामला अब सिर्फ लाइटें हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी परियोजनाओं की कार्यप्रणाली और विभागों के बीच तालमेल की कमी का बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है।

नाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत लगाए गए थे पोल- दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी नाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत बरेली शहर के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को विकसित करने का कार्य चल रहा है। करीब 200 करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य शहर के सात प्रमुख शिव मंदिरों को जोड़ना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना था। इसी योजना के अंतर्गत कुदेशिया पुल से जीआरएम स्कूल मार्ग सहित कई प्रमुख सड़कों पर भगवान शिव के प्रतीक त्रिशूल, डमरू और ॐ की आकृतियों वाले विशेष डिजाइनर पोल लगाए गए थे। इन पोलों पर आधुनिक लाइटें लगाकर पूरे मार्ग को धार्मिक थीम पर सजाया गया था। वर्ष 2025 में इस परियोजना के तहत कुल 80 विशेष डिजाइनर लाइटें लगाई गई थीं। अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक लाइट पर लगभग 70 हजार रुपये खर्च किए गए थे। इस हिसाब से केवल लाइटों पर ही करीब 56 लाख रुपये खर्च हुए।

अब सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाई जा रहीं लाइटें-अब सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। सड़क को चौड़ा करने के लिए नैनीताल रोड सहित कई मार्गों पर लगे इन्हीं डिजाइनर पोलों और लाइटों को हटाया जा रहा है।

बरेली में PM मोदी पर टिप्पणी से सियासी संग्राम, BJP का कलेक्ट्रेट पर हल्लाबोल

» सपा सांसद से माफी की मांग, भाजपा बोली- "प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा देश"

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) प्रधानमंत्री Narendra Modi पर समाजवादी पार्टी के एक सांसद द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बरेली की सियासत गरमा गई। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार धरना-प्रदर्शन करते हुए सपा सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान बताया। सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर में जुटने लगे। हाथों में तख्तियां और पार्टी के झंडे लिए कार्यकर्ताओं ने "सपा सांसद माफी मांगो", "लोकतंत्र का अपमान बंद करो" और "प्रधानमंत्री का सम्मान करो" जैसे नारों के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान माहौल पूरी तरह राजनीतिक नारों और विरोध के स्वर से गूंजता रहा। धरने का नेतृत्व कर रहीं जिला पंचायत अध्यक्ष Rashmi Patel ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल किसी दल के नेता नहीं, बल्कि देश की 140 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना सपा की कुंठित और नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है। रश्मि पटेल ने कहा, "देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। भाजपा ऐसे बयान को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी।" भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी लगातार राजनीतिक शिष्टाचार की सीमाएं लांघ रही है और जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। प्रदर्शन में मौजूद नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की वैश्विक छवि को मजबूत किया है और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाले जनप्रतिनिधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक मर्यादाएं बनी रहें। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल से ज्ञापन प्राप्त कर मामले को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों से पहले प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी का स्तर लगातार तीखा होता जा रहा है। ऐसे में नेताओं की भाषा और राजनीतिक संवाद को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। भाजपा जहां इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के सम्मान से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिक्रिया बता रहा है। फिलहाल बरेली में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

रामपुर में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप

थानागंज क्षेत्र के नानकार निवासी माहिम की मौत से मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

लोकतंत्र की शान

रामपुर : रामपुर के थानागंज क्षेत्र के निकट नानकार निवासी युवक माहिम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने युवक की मौत को साजिशन हत्या बताते हुए उसके दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि माहिम को घर से बुलाकर कुछ दोस्त अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद उसकी मौत की खबर मिली। परिजनों ने आरोप लगाया कि साथ ले जाने वाले दोस्तों ने ही माहिम की हत्या की है। परिजनों का यह भी कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे थाने में तहरीर देने और उचित कार्रवाई की मांग करते रहेंगे। वहीं, आसपास के लोगों का कहना है कि यह मामला सड़क हादसे (एक्सीडेंट) का हो सकता है, लेकिन परिजन इसे मानने को तैयार नहीं हैं। लोगों का कहना है कि घटना की सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मृतक के दोस्तों से पूछताछ और घटनास्थल की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

योगी सरकार ने आयुष्मान योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए चलाया विशेष अभियान

लोकतंत्र की शान

खनऊ : योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) के तहत अस्पतालों और चिकित्सकों के डाटा को और अधिक सटीक बनाने के लिए विशेष सत्यापन एवं सैनेटाइजेशन अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य योजना के लाभार्थियों को सुरक्षित, पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

अस्पतालों एवं चिकित्सकों से जुड़े डाटा का किया गया परीक्षण-साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। साथ ही किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना को समाप्त किया जा सके। ऐसे में विभाग की ओर से तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। हाल ही में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान अस्पतालों एवं चिकित्सकों से जुड़े डाटा का गहन परीक्षण किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि 28 चिकित्सकों के नाम 15 से अधिक अस्पतालों से जुड़े हुए थे, जबकि 274 चिकित्सकों के नाम सात से अधिक अस्पतालों में दर्ज पाए गए। इस पर संबंधित चिकित्सकों एवं अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए और तीन दिवसीय सत्यापन प्रक्रिया संचालित की गई। इस दौरान सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने तथा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया।

सीएम योगी की प्रेरणा से ईंधन बचत अभियान को मिली नई रफ्तार, साइकिल से विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री

लोकतंत्र की शान

लखनऊ। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसका पालन पूरे प्रदेश में करने पर जोर दिया था। इसके बाद इस मुहिम का प्रदेशव्यापी असर देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री से लेकर पार्षद तक इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सराहनीय पहल की है। गुरुवार को उन्होंने अपने सरकारी आवास 10 कालिदास मार्ग से विधानसभा स्थित कार्यालय तक साइकिल से पहुंचकर ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश दिया। आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया।

सप्ताह में एक दिन साइकिल से कार्यालय जाने का लिया संकल्प-मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वह प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक दिन साइकिल से कार्यालय जाएंगे, ताकि आम लोगों को भी ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 85 से 86 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पाद विदेशों से आयात किए जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। ऐसे में ईंधन की बचत केवल आर्थिक मजबूती ही नहीं, बल्कि राष्ट्रहित से भी जुड़ा विषय है।

जनभागीदारी से मजबूत हो रहा ऊर्जा संरक्षण अभियान- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दे रही है। मंत्री सुरेश खन्ना की यह पहल योगी सरकार की उसी सोच को आगे बढ़ाने वाली मानी जा रही है। साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देकर सरकार स्वस्थ जीवनशैली और प्रदूषण नियंत्रण का भी संदेश दे रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इस पहल को सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

हवाई हमले से बचाव का मॉकड्रिल, आज शाम 7 बजे से 15 मिनट तक रहेगा ब्लैक आउट

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली में आज हवाई हमले से बचाव के लिए 'ब्लैक आउट मॉकड्रिल' का आयोजन किया जा रहा है। यह पूर्वाभ्यास असैनिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के निर्देशानुसार शाम 07:00 बजे से 07:15 बजे तक चलेगा। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने इसकी जानकारी दी। मॉकड्रिल से ठीक पहले शाम 06:58 बजे दो मिनट के लिए सायरन बजेगा। इसके बाद, शाम 07:00 बजे से 07:15 बजे तक जिले के निर्धारित क्षेत्रों में पूर्ण ब्लैक आउट रहेगा। इस दौरान आम नागरिकों से सभी प्रकार की लाइटें बंद रखने का अनुरोध किया गया है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मॉकड्रिल की अवधि में घरों, प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों पर बिजली, जनरेटर, इन्वर्टर, मोबाइल फ्लैशलाइट, टॉर्च या किसी भी अन्य प्रकाश उपकरण का उपयोग न किया जाए। सड़कों पर चलने वाले वाहनों को भी रोककर उनकी लाइटें बंद रखने को कहा गया है। महात्मा गांधी सेतु पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय पर सेतु पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित करें। इन अधिकारियों को वाहनों को रोककर उनकी लाइटें बंद करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वैशाली नहीं पहुंचे चिराग पासवान, बाबा चौहरमल कार्यक्रम में राज्य सरकार के 3 मिनिस्टर पहुंचे

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली जिले के महुआ में आयोजित बाबा चौहरमल कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नहीं पहुंचने पर लोगों में नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्रियों को मंच पर ही खरी-खोटी सुनाई गई। यह कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इंतजार में एक महीने के लिए टाल दिया गया था। उनके न आने पर बिहार सरकार के तीन मंत्री लखेंद्र पासवान, संजय पासवान और संजय सिंह कार्यक्रम में पहुंचे। हालांकि, दो मंत्री कार्यक्रम समाप्त होने से पहले ही वहां से चले गए, जबकि स्थानीय विधायक और मंत्री संजय सिंह मौजूद रहे। चिराग पासवान के न पहुंचने से नाराज कार्यकर्ताओं ने मंच पर मौजूद मंत्रियों को खरी-खोटी सुनाना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप था कि चिराग पासवान के कारण ही कार्यक्रम एक महीने आगे बढ़ाया गया, जिस पर महुआ के गांधी मैदान में पंडाल लगाने में लाखों रुपये खर्च हुए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर उन्हें नहीं आना था, तो कार्यक्रम पहले ही कर लिया जाता। मंत्री संजय सिंह ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और बताया कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कैबिनेट की बैठक के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। हालांकि, नाराज कार्यकर्ता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और लगातार सवाल कर रहे थे कि जब चिराग पासवान को नहीं आना था, तो उन्होंने समय क्यों दिया। काफी देर तक समझाने के बाद भी जब लोग शांत नहीं हुए, तो मंत्री संजय सिंह कार्यक्रम स्थल से निकल गए। इसके बाद भी महुआ के गांधी मैदान में कार्यक्रम कुछ देर तक चला और फिर उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई।

सराय थाना के पास जब्त गाड़ी से ऑटो टकराया, 12 से अधिक लोग घायल, ड्राइवर बोला- आंख में गया था कीड़ा

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली जिले में हाजीपुर-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर सराय थाना के पास एक सड़क दुर्घटना में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। एक सीएनजी टेम्पो ने पुलिस द्वारा जब्त किए गए एक खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और सराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर ले जाया गया। जानकारी के अनुसार, सभी घायल मुजफ्फरपुर जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र से हाजीपुर आ रहे थे। वे मोहम्मदपुर मुबारक गांव निवासी अनिल शाह की बेटी तुलसी कुमारी की शादी में शामिल होने के लिए पातालेश्वर मंदिर जा रहे थे। टक्कर में टेम्पो सवार किसुन साह, सूरज कुमार, सुशील शाह, कैलाश शाह, आदित्य कुमार, देव कुमार, प्रकाश कुमार, लक्ष्य कुमार और आनंद कुमार सहित एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायल प्रकाश कुमार ने बताया कि वे अपनी बहन तुलसी कुमारी की शादी में शामिल होने जा रहे थे। घायल किशन शाह ने बताया कि चालक ने बताया कि आंख में कीड़ा पड़ने के कारण यह हादसा हुआ। सराय थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने पुष्टि की कि सभी घायल एक टेम्पो पर सवार होकर मुजफ्फरपुर से हाजीपुर शादी समारोह में जा रहे थे। टेम्पो को जब्त कर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

प्राइवेट पार्ट में खून, 3 उंगलियां कटीं, पसलियां तोड़ीं, 2 बच्चियों की रेप के बाद मर्डर की आशंका

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में 11 मई को लापता बहनों की लाश बुधवार(13 मई) को ईंट भट्ठे के पास मिली थी। मौत कैसे हुई इसको लेकर अभी जांच चल रही है। लेकिन परिवार वालों का दावा है कि बच्चियों के साथ रेप करने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या की गई है। मृतकों की उम्र 7 और 12 साल है। वहीं, पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक हत्या 11 मई को ही की गई है। डॉक्टर्स रेप के बाद हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। दोनों बच्चियां मीनापुर थाना क्षेत्र से लापता हुई थीं और शव रामपुर हरि थाना इलाके से बरामद हुए। पोस्टमॉर्टम में शामिल डॉक्टर्स के मुताबिक, एक बच्ची, जिसकी उम्र 12 साल है। उसके प्राइवेट पार्ट पर खून मिला है। रेप की आशंका पर वेजाइनल स्वाब को सुरक्षित रखा गया है। बच्चियों का पहले गला दबाया गया, उसके बाद गला रेतकर उनकी हत्या की गई। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि, बच्ची के बाएं हाथ की 3 उंगुलियां भी कटी मिली हैं। जबड़ा भी निकला था। सीने पर किसी भारी चीज से हमला हुआ है। जिसकी वजह से फेफड़े की चार हड्डियां टूटी गई हैं। चिकित्सकों ने खून से सने कपड़े पुलिस को हैंडओवर कर दिए हैं। बच्चियों के परिवार वालों का कहना है कि, रेप के बाद हत्या की गई है। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर्स भी रेप के बाद हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं पुलिस की थ्योरी अलग है। पुलिस का कहना है कि जहां दोनों बच्चियों की लाश मिली है। उस इलाके के 13 CCTV को खंगाला गया है।

पुलिस का कहना है कि फुटेज में बच्चियां उस रास्ते पर जाते दिख रही हैं जहां आगे एक गड्ढा है। वो दोनों पानी भरे गड्ढे में गिर जाती हैं। पुलिस का कहना है कि गड्ढा करीब 5 फीट गहरा था और सोमवार को उसमें काफी पानी भरा हुआ था। आशंका है कि दोनों बच्चियां उसी में डूब गईं। बड़ी बच्ची के शव पर मिले गहरे जख्म को लेकर पुलिस का कहना है कि पानी में डूबने के बाद लाश पानी के स्तह पर आ गई होगी। इस दौरान किसी जानवर के नोंचने से ऐसे निशान बने होंगे। हालांकि, पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद सही जानकारी सामने आ पाएगी। मृत बच्ची(12) की मां का कहना है, 'मेरी बेटी 5वीं क्लास में पढ़ती थी। हमारा गांव में किसी से कोई विवाद नहीं था। 11 मई को मेरी बेटी अपनी चचेरी छोटी बहन के साथ घर के बाहर खेल रही थी। उस दिन गांव में शादी भी थी। दोनों का शादी वाले घर के आस-पास आना-जाना भी लगा था। इसी दौरान उसे कोई उठा ले गया और मारकर ईंट भट्ठे के पास फेंक दिया। मेरी बेटी को बेरहमी से पीट-पीटकर मारा गया है। बच्ची के दांत तक तोड़े गए हैं। उसके शरीर चोट के निशान हैं। लापता होने के बाद पुलिस को सूचना दी थी। हमें जान के बदला जान चाहिए। जिसने भी ये किया है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए।' वहीं दूसरी बच्ची(7) के पिता ने बताया कि, 'जब बच्ची लापता हुईं तो हमलोगों ने दोनों की काफी खोजबीन की थी। जहां लाशें मिली वहां भी देखा था, पर दोनों नहीं मिली थीं। बाद में दोनों की लाशें वहीं मिलीं। किसी ने हत्या के बाद फेंक दिया है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है कि किसी पर आरोप लगा सके।'

विश्व साइकिलिंग दिवस पर सहरसा में जिला साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः विश्व साइकिलिंग दिवस के अवसर पर आगामी 1 से 3 जून 2026 तक जिला साइकलिंग संघ सहरसा के तत्वावधान में जिला साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन सहरसा स्टेडियम में किया जाएगा। प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला साइकलिंग संघ के सचिव दर्शन कुमार गुड्डू ने बताया कि तीन दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान साइकिलिंग की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें पारितोषिक देकर सम्मानित भी

किया जाएगा। जिला साइकलिंग संघ के अध्यक्ष डॉ जयंत आशीष ने कहा कि साइकिलिंग स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है और यह खेल युवाओं को बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप साइकिलिंग को अपनाकर लोग डीजल और पेट्रोल की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसी उद्देश्य से जिला साइकिलिंग संघ द्वारा साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं जिला साइकिलिंग संघ के संरक्षक रौशन सिंह धोनी ने कहा कि साइकिलिंग के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग एक ओलंपिक खेल है और इसके माध्यम से बच्चे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकते हैं। साथ ही साइकिलिंग से स्वास्थ्य बेहतर होता है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है तथा ईंधन की बचत भी होती है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए निबंधन अनिवार्य किया गया है। निबंधन पूरी तरह निशुल्क होगा। निबंधन फॉर्म साई सुपर मार्केट, सहरसा से प्राप्त एवं वहीं जमा किया जा सकता है। निबंधन की अंतिम तिथि 28 मई 2026 निर्धारित की गई है।

बच्चे देखेंगे साइंस का जादू, श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र में 24 मई से समर हॉबी कैंप

ब्रह्मांड में छिपे राज को समझने का मौका

लोकतंत्र की शान, पटना

पटना के श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र में बच्चे साइंस का जादू देखेंगे। यहां 24 मई से समर वेकेशन हॉबी कैंप की शुरुआत हो रही है। क्लास 4 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए अलग-अलग वर्कशॉप कराए जाएंगे। इस हॉबी कैंप में ब्रह्मांड में छिपे राज से लेकर मानव जीवन की यात्रा के बारे में बताया जाएगा। कैंप का आयोजन दो सेशन में होगा। पहला मॉर्निंग सेशन होगा, जो सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 तक चलेगी। दूसरा इवनिंग सेशन होगा, जो दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी।

स्पेशली स्कूली बच्चों के लिए तैयार किया गया कैंपः यह कैंप स्कूली बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिसमें विज्ञान और तकनीक से जुड़े विषयों पर प्रयोग आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कैंप के दौरान कॉस्मिक वंडर्स, बायो क्वेस्ट, बिल्ड एंड लर्न, ग्रो विदाउट सॉयल, कोड एंड क्रिएट, फिजिक्स इन योर हैंड्स, केमिस्ट्री इन

कलर्स और नंबर्स एंड बियॉन्ड जैसी वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी। हर वर्कशॉप के लिए अलग-अलग तिथि, आयु सीमा और शुल्क निर्धारित किया गया है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं छात्रः इस कैंप में बच्चों को खगोल विज्ञान, जीवन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, गणित, रोबोटिक्स, रसायन विज्ञान और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे विषयों की जानकारी सरल और रोचक तरीके से दी जाएगी। विज्ञान केंद्र के परियोजना निदेशक श्रीनू अप्पिकोंडा ने बताया कि, 'कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है। इच्छुक छात्र https://tinyurl.com/ssc-SummerCamp ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।'

लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन एवं उत्कृष्ट कार्यालय प्रबंधन पर जोर

लोकतंत्र की शान

सहरसा, Mohammad जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः स्थानीय विकास भवन में गुरुवार को जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय, प्रखंड, अंचल एवं बाल विकास परियोजना कार्यालयों के प्रधान सहायकों एवं नाजिरों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्धारित कार्यों के सम्यक निष्पादन तथा उत्कृष्ट कार्यालय प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। बैठक के दौरान लंबित पत्रों, रोकड़ पंजी, जनशिकायतों, माननीय न्यायालय से संबंधित मामलों, अंकेक्षण, सेवांत लाभ एवं विभागीय कार्रवाई से जुड़े प्रतिवेदनों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में कई कार्यालयों में उपर्युक्त मामलों से संबंधित लंबित एवं अप्राप्त प्रतिवेदन पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यालयों को सेवांत लाभ, विभागीय कार्रवाई, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जनशिकायतों, न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों तथा अंकेक्षण से जुड़ी आपत्तियों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सभी कार्यालयों को रोकड़ पंजी एवं अन्य अभिलेखों का समुचित संधारण सुनिश्चित करने तथा कार्यालय प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता निशांत, स्थापना उप समाहर्ता अभिनव भास्कर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

सहरसा जिले में फार्मर रजिस्ट्री विशेष शिविर का आयोजन

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा सहरसा जिले के सभी पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष अभियान 12 मई 2026 से 30 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य जिले के सभी रैयतधारी किसानों का फार्मर आईडी बनाना है, ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं एवं कृषि संबंधी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके। जारी सूचना के अनुसार जिन किसानों का अब तक फार्मर आईडी नहीं बना है, उनका पंजीकरण इस विशेष शिविर में किया जाएगा। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में बिना फार्मर आईडी के किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं हो सकेगा। साथ ही पैक्स के माध्यम से खरीद-बिक्री की प्रक्रिया भी केवल फार्मर आईडी के आधार पर ही की जाएगी। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले में 1,48,178 किसानों का फार्मर आईडी बनाया जा चुका है, जबकि अभी भी 2,83,941 से अधिक रैयतधारी किसानों का पंजीकरण शेष है। कृषि विभाग ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं किसानों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी पंचायत में आयोजित विशेष शिविर में पहुंचकर फार्मर आईडी का निर्माण

अवश्य करा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विभाग के अनुसार फार्मर आईडी बनने से किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, उर्वरक की सुगम उपलब्धता, पैक्स के माध्यम से खरीद-बिक्री की सुविधा तथा कृषि संबंधी अन्य लाभ प्राप्त होंगे।

पटना में अंतरराज्यीय गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान, पटना

पटना के फतुहा अनुमंडल अंतर्गत नदी थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर और तस्कर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जेठुली घाट के पास से चोरी के दो पिकअप वाहन बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने एक शातिर अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुलमहियाबाग निवासी 36 वर्षीय चंदन कुमार के रूप में हुई है।

गुप्त सूचना पर हुई छापेमारीः फतुहा एसडीपीओ-1 अवधेश कुमार ने नदी थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 13 मई 2026 को दोपहर करीब 2:10 बजे दिवा गश्ती के दौरान पुलिस अवर निरीक्षक जयकिशोर चौधरी को सूचना मिली थी कि जेठुली घाट के समीप चोरी के तीन पिकअप वाहन खड़े हैं और उन पर अवैध मादक पदार्थ लोड कर तस्करी की तैयारी की जा रही

है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई।

दो चोरी के वाहन बरामदः पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर चंदन कुमार को दो चोरी के पिकअप वाहनों के साथ गिरफ्तार कर लिया। जांच में पुष्टि हुई कि दोनों वाहनों के खिलाफ पहले से चोरी की प्राथमिकी दर्ज है। बरामद वाहनों के नंबर BR06GC9070 और BR01GJ7809 बताए गए हैं।

एसडीपीओ अवधेश कुमार ने बताया कि, 'गिरोह में शामिल अन्य अज्ञात अपराधियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है।'

सहरसा के घरों तक अब पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस, सोमवार से योजना की शुरुआत

लोकतंत्र की शान

सहरसा, Mohammad जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः सहरसा शहरवासियों का पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस (PNG) उपलब्ध होने का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। जिला आपूर्ति शाखा, सहरसा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आगामी सोमवार सुबह 10 बजे इस महत्वाकांक्षी योजना का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर के एक चयनित घरेलू उपभोक्ता के घर में चूल्हा जलाकर योजना की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त (DDC), अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा नगर आयुक्त सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सिटी गैस परियोजना से जुड़े इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के प्रतिनिधियों ने योजना की वर्तमान प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। बैठक के दौरान

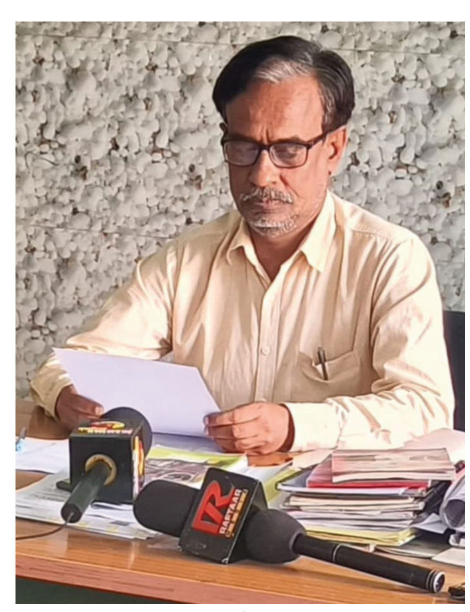

बताया गया कि पाइपलाइन की सुरक्षा एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रविवार शाम 5 बजे तक सभी आवश्यक परीक्षण एवं उपकरणों की जांच पूरी कर ली जाएगी। समीक्षा बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सहरसा के पश्चिमी क्षेत्र में पाइपलाइन विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है तथा कंपनी का लक्ष्य आगामी एक माह के भीतर पश्चिमी क्षेत्र में भी गैस आपूर्ति प्रारंभ करना है। जिलाधिकारी ने इंडियन ऑयल के अधिकारियों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को कनेक्शन से संबंधित तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु त्वरित सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्रशासन के अनुसार पाइपलाइन गैस योजना शुरू होने से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी की प्रतीक्षा से राहत मिलेगी। साथ ही यह सुविधा पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर की तुलना में अधिक सुरक्षित एवं किफायती साबित होगी।

कोरोना नियम उल्लंघन मामले में तेजस्वी को जमानत

लोकतंत्र की शान, पटना

कोरोना काल में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आज पटना के एमपी/एमएलए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत में तेजस्वी ने आत्मसमर्पण कर जमानत की मांग की। अदालत ने तेजस्वी यादव को जमानत दे दिया है। सुनवाई के बाह तेजस्वी यादव बाहर आए और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि, 'कोविड के समय का पुराना धरना प्रदर्शन का मामला था, जो सरकार धरना प्रदर्शन को लेकर फर्जी केस करती है, वही सब था। जिस समय लोग मजदूर परेशान थे। जिंदगी जा रही थी। इसी जन समस्या को लेकर हम लोगों की ओर से आवाज उठाई गई थी। जिसे लेकर सरकार की ओर से फर्जी मुकदमा किया गया था। इसी सिलसिले में पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिली है।

दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि विजन नहीं है। कल को कहेंगे कपड़ा मत पहनिए...समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और सरकार की होती है। पहले भी इन्होंने नोटबंदी के समय अपील की थी। लेकिन इसका क्या फायदा हुआ। हम तो जानना चाहते हैं। कई लोगों का नुकसान हुआ। कई लोग

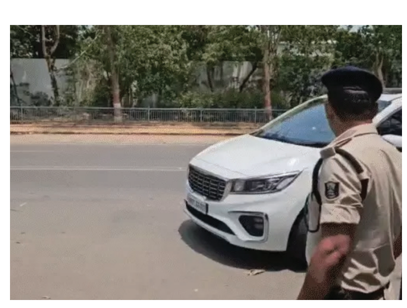

बेरोजगार हो गए। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बंद हो गई। प्रधानमंत्री इसी तरीके की बात करते रहेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। कोई रोड मैप विजन नहीं है। कोरोना काल में कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में दर्ज केस में तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद पटना के एमपी/एमएलए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

'जन समस्याओं की आवाज उठाने पर हुआ केस': सुनवाई के बाद कोर्ट परिसर से बाहर निकलते हुए तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह कोविड काल के दौरान धरना-प्रदर्शन से जुड़ा पुराना मामला था। उन्होंने कहा, "सरकार धरना-प्रदर्शन को लेकर फर्जी केस करती

पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, बोले- मजदूरों की आवाज उठाने पर हुआ था फर्जी केस

है। उस समय मजदूर परेशान थे, लोगों की जिंदगी जा रही थी। उन्हीं जन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने आवाज उठाई थी। इसी वजह से सरकार की ओर से फर्जी मुकदमा किया गया था। अब उसी मामले में पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिली है।"

इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास समस्याओं के समाधान का कोई विजन नहीं है। तेजस्वी ने कहा, "कल को कहेंगे कपड़ा मत पहनिए। समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और सरकार की होती है। नोटबंदी के समय भी अपील की गई थी, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ?" उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी के कारण कई लोगों का नुकसान हुआ, बेरोजगारी बढ़ी और छोटे-मझोले उद्योग बंद हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्दों की बात नहीं करते और देश के सामने मौजूद समस्याओं पर कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है।

पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों को मिलेगी एक साथ दो डिग्री

लोकतंत्र की शान, पटना

अब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र एक ही समय में दो अलग-अलग डिग्री हासिल कर सकेंगे। पटना यूनिवर्सिटी में आज सिंडिकेट की बैठक है। इस बैठक में 'डुअल डिग्री कोर्स' पर चर्चा होगी। मंगलवार को एकेडेमिक काउंसिल की बैठक में जिन प्रस्तावों को पास किया गया था, उसे आज सिंडिकेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद 23 मई को सीनेट की बैठक में इसपर फाइनल मुहर लगेगी। सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे राजभवन भेजा जाएगा, जहां फाइनल अनुमति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

ऑफलाइन-ऑनलाइन कर सकेंगे ड्युअल डिग्री कोर्सः PU के एकेडमिक काउंसिल हॉल में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार छात्र अब दो डिग्री प्रोग्राम में एक साथ नामांकन ले सकेंगे। इसके तहत

स्नातक के छात्र तीन या चार साल के डिग्री कोर्स के साथ रोजगारपरक कोर्स कर सकते है। उसी तरह पीजी के दो वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ छात्र भी वोकेशनल कोर्स कर सकेंगे। इसमें शर्त यह होगी कि एक कोर्स 'ऑफलाइन' में होगा, जबकि दूसरा कोर्स 'ऑनलाइन' में करना होगा। हालांकि, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि पीएचडी करने वाले छात्र इस ड्युअल डिग्री योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही पीयू में सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स को भी मंजूरी दी गयी थी।

संक्षिप्त समाचार

सोनीपतः मेयर ने पेयजल की किल्लत पर अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार

लोकतंत्र की शान : सोनीपत। सोनीपत मेयर चुनाव लगातार दूसरी बार जीतने के बाद राजीव जैन अगले ही दिन एक्शन मोड में दिखाई दिए। गुरुवार को उन्होंने पार्षदों के साथ शहर के वाटर बूस्टिंग स्टेशनों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति किसी भी हाल में बाधित नहीं होनी चाहिए। निरीक्षणके दौरान कालूपुर चुंगी के पास बने नए बूस्टिंग स्टेशन से कई महीनों बाद भी पानी की सप्लाई शुरू न होने पर मेयर ने फोन पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सभी बूस्टिंग स्टेशनों का तुरंत निरीक्षण किया जाए और दो दिनों के भीतर कमियों को दूर कर रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने साफ कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता नहीं भुगतेगी। पार्षदों से भी अपने-अपने वार्ड के बूस्टिंग स्टेशनों पर नजर रखने को कहा गया। मेयर पार्षद संजय ठेकेदार और राजकुमार शर्मा के साथ कालूपुर के नए बूस्टिंग स्टेशन पहुंचे तो वहां ताला बंद मिला। अधिकारियों ने बताया कि यहां लगी दोनों मोटर पच्चीस हॉर्स पावर क्षमता की हैं, जो दबाव से पानी नहीं उठा पा रही हैं। इस पर मेयर ने तुरंत चालीस हॉर्स पावर की मोटर लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद मुरथल गांव स्थित पम्प हाउस का निरीक्षण किया गया। यहां सात में से केवल दो ट्यूबवेल चालू मिले। तीन ट्यूबवेल ट्रांसफार्मर खराब होने से बंद थे, जबकि दो ट्यूबवेल का जल स्तर नीचे जा चुका है। मेयर ने सभी सात ट्यूबवेल जल्द चालू करने के निर्देश दिए ताकि बरसात के दिनों में जाजल क्षेत्र में आने वाली समस्या के समय शहर को निर्बाध पेयजल आपूर्ति हो सके। महलाना रोड स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर खराब ट्रांसफार्मर को भी तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए गए। मेयर ने कहा कि भीषण गर्मी से पहले सभी कमियां दूर कर लोगों को पानी की किल्लत से बचाना प्राथमिकता है।

सोनीपतः बाबा हरदेव सिंह का जीवन मानवता व सेवा का देता है संदेशःसुदीक्षा महाराज

लोकतंत्र की शान : सोनीपत। समालखा-गन्नौर हल्दाना बॉर्डर स्थित मैदान में बुधवार रात संत निरंकारी मिशन द्वारा बाबा हरदेव सिंह की स्मृति में संत समागम आयोजित किया गया। श्रद्धा और भक्ति से भरे इस आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज और निरंकारी राजपिता रमित की उपस्थिति रही। श्रद्धालुओं ने सतगुरु के दर्शन कर प्रवचनों को सुना और आत्मिक शांति व प्रेरणा का अनुभव किया। सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने कहा कि बाबा हरदेव सिंह का जीवन मानवता, सेवा और प्रेम का संदेश देता है। श्रद्धालुओं के हृदय में जीवित है। वर्तमान में उनके संदेशों को आगे बढ़ाते हुए सेवा, समर्पण और सद्भाव का प्रकाश फैलाना विश्व में मानवता, एकता और भाईचारे का संदेश निरंतर प्रसारित करना है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन का हर क्षण सार्थक बनाते हुए इंसानियत और करुणा के मूल्यों को अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपने भीतर मानवीय गुण विकसित कर निराकार का सहारा लेकर उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। सतगुरु माता ने कहा कि ब्रह्मज्ञान मिलने के बाद जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि पूरी मानवता की सेवा का माध्यम बन जाता है। सच्ची सेवा दिखावे से दूर प्रेम और निस्वार्थ भाव से की जाती है। वास्तविक भक्ति शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार और कर्मों में दिखाई देती है। उन्होंने अमर संत अवनीत के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि सच्चा समर्पण वही है जो जीवन की प्राथमिकताओं में दिखाई दे। गृहस्थ जीवन निभाते हुए भी सेवा और भक्ति को प्राथमिकता दी जा सकती है। समागम के दौरान गीतकारों, कवियों और विचारकों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। सभी प्रस्तुतियों में बाबा हरदेव सिंह की शिक्षाओं और उनके सेवा भाव का उल्लेख रहा। श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम को भावपूर्ण और प्रेरणादायक बताया। अंतमें आशीर्वाद देते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने कहा कि हर व्यक्ति सेवा, सुमिरण और सत्संग को जीवन में अपनाए और प्रेम व शांति का संदेश फैलाए।

मोहाली नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड 40 से भाजपा उम्मीदवार के पिता पर हमला

लोकतंत्र की शान : मोहाली। मोहाली नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 40 से भाजपा उम्मीदवार के पिता पर हमले की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। भाजपा उम्मीदवार गौतम गिरीश लद्दड़ के पिता रिटायर्ड आईएएस एसआर लद्दड़ सेक्टर 77 में घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात युवकों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान एस आर लद्दड़ जमीन पर गिर पड़े, जिससे उन्हें हल्की चोटें भी आई हैं। हमलावरों ने उन्हें धमकाया कि वे दोबारा सेक्टर 77 में प्रवेश न करें। घटना के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और लद्दड़ ने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं। इस मामले पर भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव विशिष्ट ने बताया कि सुबह करीब 8:30 बजे उन्हें उम्मीदवार की ओर से फोन आया, जिसमें इस हमले की जानकारी दी गई। विशिष्ट ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय लोगों ने जबरदस्ती करते हुए धक्का-मुक्की की और धमकाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एसएसपी मोहाली हरमदीप सिंह हंस और डीएसपी सिटी-2 हरसिमरन सिंह बल्ल से बात हो चुकी है, जिन्होंने आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। विशिष्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे डरें नहीं और किसी भी तरह की धमकी की जानकारी तुरंत साझा करें।

सम्मानित होंगे हथकरघा बुनकर

लोकतंत्र की शान : जयपुर। राज्य के हाथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नकद पुरस्कार दिए लाएंगे। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र जयपुर (ग्रामीण) के महाप्रबंधक सुभाष चन्द्र शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए जिले की सीमा में कार्यरत हाथकरघा बुनकरों से आवेदन पत्र आमंत्रित है। इसके लिए वहीं बुनकर पात्र हैं जो हाथकरघा पर बुनाई कार्य में पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रहे हैं तथा जिन्हें गत 3 वर्षों में इस पुरस्कार के लिए चयनित नहीं किया गया हो। पात्र हाथकरघा बुनकर अपना आवेदन गुरुवार 15 मई 2026 तक कार्यालय महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र जयपुर (ग्रामीण) में जमा करा सकते हैं। आवेदन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

भारतीय सेना भर्ती : ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी

लोकतंत्र की शान " जयपुर। भारतीय सेना में भर्ती वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) 01 जून से 12 जून 2026 तक राजस्थान के ग्यारह शहरों अजमेर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, सीकर और उदयपुर में 32 केंद्रों पर आयोजित होगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने शुरू हो गए है और सम्बंधित उम्मीदवार 15 मई से ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट (www.joinindianarmy.nic.in) से एडमिट कार्ड डाऊनलोड कर सकते है। जन संपर्क अधिकारी (रक्षा) लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने जानकारी दी कि ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) तिथिवार कार्यक्रम ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अग्निवीर (सामान्य ड्यूटी), अग्निवीर (तकनीकी), अग्निवीर (कार्यालाय सहायक/स्टोर कीपर तकनीकी), अग्निवीर ट्रेडसमैन (10वी और 8वी पास), अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (महिला सेना पुलिस), सैनिक तकनीकी (एनए/ एनए चिकित्सा), सिपाही फार्मा, हवलदार शिक्षा (सूचना और तकनीक/ साइबर, सूचनात्मक कार्यवाही और भाषाविद) और धार्मिक शिक्षक जूनियर कमीशन अधिकारी श्रेणियों के लिए प्रदर्शित किया गया है। किसी भी सहायता या प्रश्न के लिए संभावित उम्मीदवार अपने सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क करें | जिनके संपर्क और पते का विवरण भारतीय सेना के ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं |

खनिज-पुलिस की संयुक्त कार्वाई अवैध खनिज परिवहन में 3 वाहन जब्त

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा जिला खनिज अधिकारी कपिलमुनि शुक्ला के मार्गदर्शन में खनिज एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा सिहावल तहसील अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु सघन जांच अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान खनिज गिट्टी एवं रेत के अनाधिकृत परिवहन में संलिप्त 3 वाहनों को जब्त कर सुरक्षार्थ थाना अमिलिया में खड़ा कराया गया। जांच के दौरान ग्राम हर्दी, तहसील सिहावल में डंपर क्रमांक MP53GA3424 को खनिज गिट्टी का अनाधिकृत परिवहन करते हुए पकड़ा गया, जिसे नियमानुसार जब्त कर थाना अमिलिया में सुरक्षित रखा गया। इसी प्रकार थाना अमिलिया के सामने जांच के दौरान डंपर क्रमांक MP53ZC3314 तथा बिना नंबर की 12 चक्का हाइवा (चेसिस क्रमांक MAT569002R3K28648) को रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त पाया गया। दोनों वाहनों को भी नियमानुसार जब्त कर थाना प्रभारी अमिलिया की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। संबंधित वाहन चालकों एवं स्वामियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं, बिना नंबर वाहनों से खनिज परिवहन किए जाने के मामले में वाहन स्वामियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए जिला परिवहन अधिकारी सीधी को पृथक से पत्र प्रेषित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार नजर रखी जा रही है। कहीं भी अवैध गतिविधियां पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

वन क्षेत्र से जारी है रेत का अवैध कारोबार

रेंजर,डिप्टी व विभाग सवालों के घेरे में

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के तहसील क्षेत्र मझौली अंतर्गत सामान्य वन परिक्षेत्र,संजय टाइगर रिजर्व एवं सोन घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमाएं लगती हैं जहां रेत का कारोबार जारी है जिस कारण रेंजर,डिप्टी रेंजर एवं विभाग भी सवालों के घेरे में देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो सामान्य वन परिक्षेत्र के सीमा चमराडोल, बोदारी टोला, परसिली, नौढ़िया, सेमारिहा, छुही,तिलवारी,पांड,पोड़ी,खमचौरा से रेत निकासी का कारोबार हो रहा है। इसी तरह सोन घड़ियाल एवं संजय टाइगर रिजर्व की सीमा से भी रेत निकासी की जाती है लेकिन संबंधित विभाग कुम्भकरणी नीद मे सोया हुआ है। सूत्रों की माने तो वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री मिश्रा की पदस्थापना पर लोगों मे उम्मीद जगी थी की वन सीमा से उत्तखनन व परिवहन पर उनके द्वारा सिकंजा कसा जाएगा व रेत के कारोबार मे लगाम लगेगा लेकिन दो चार महीनों मे इक्का दुक्का नामचार के लिए कार्यवाही उनके क्रिया कलापों पर भी सवाल खड़ा करती हैं की जब रोज लगभग आधा सैंकड़ा वाहन जंगलों से रेत निकाल रहें हैं तो उनपर कार्यवाही से परहेज क्यों। जानकारों की माने तो नदी नालों से अंधाधुंध रेत निकासी के कारण दिनों दिन जलस्तर नीचे जा रहा है इस कारण वन्यजीव एवं जल जीवन पर खतरा मंडरा रहा है।

24 छात्रों को मिली मेरिट 55 बच्चों ने प्रथम श्रेणी में पास

लोकतंत्र की शान, राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट

करनालः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में एस.डी. सी.सै.स्कूल के छात्रों ने 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम लाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 100 छात्रों में से 24 छात्रों ने मैरिट तथा 55 ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की हैं। दसवीं कक्षा के छात्र दिलीप ने 95.6% अंक प्राप्त करके विद्यालय में प्रथम स्थान तथा छात्रा मनीषा ने 92.2% अंक प्राप्त करके द्वितीय, नमन ने 90.6% अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया तथा काजल ने 88.8%, लविश ने 88.6% देव ने 87.6% निचिकेत ने 86%, नमन पांचाल ने 85.4% तथा रमन ने 85.4% अंक प्राप्त किए। प्रथम आए छात्र दिलीप ने साईंस तथा संस्कृत में 98 अंक, गणित में 95 अंक एवं हिन्दी में 91 अंक प्राप्त कर विशेष उपलब्धि हासिल की है। समीर छात्र ने सामाजिक विज्ञान में 98 अंक, लविश ने शारीरिक शिक्षा में 95 अंक एवं हिन्दी में 91 अंक, तनिष ने पंजाबी में 92 अंक तथा निचिकेत ने अंग्रेजी विषय में 91 अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर प्रबंधक समिति के प्रधान रविन्द्र सिंह भाटिया जी तथा अन्य सदस्यों ने इन प्रतिभागीशाली विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं दीं। इस खुशी से गदगद होकर प्रधानाचार्या रेनू गुप्ता ने भी विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें विद्यार्थियों की इस सफलता पर गर्व है, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जो विद्यार्थी जीवन में परिश्रम करते हैं सफलता उनके कदम अवश्य ही चूमती हैं।

किसानों के साथ विश्वासघात कर रही भाजपा सरकारः कमलेश्वर

» गेहूं खरीदी व्यवस्था ध्वस्तए सर्वर फेल होने से किसान दर दर भटकने को मजबूर

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। प्रदेश में भाजपा सरकार की किसान हितैषी नीतियों की सच्चाई अब किसानों के सामने खुलकर आ चुकी है। एक ओर सरकार मंचों से किसानों की आय दोगुनी करने और हर दाना खरीदने के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश का किसान अपनी उपज बेचने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल खराब कर उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया और अब सरकार की अव्यवस्थित गेहूं खरीदी व्यवस्था किसानों की परेशानी और बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं उपार्जन पंजीयन के दौरान लगातार सर्वर फेल होने से हजारों किसान पंजीकरण से वंचित रह गए। जिन किसानों का पंजीयन हो चुका है, उन्हें स्लॉट बुकिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसान सुबह से शाम तक सोसायटियों और ऑनलाइन केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पोर्टल खुल नहीं रहा और खरीदी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार केवल विज्ञापनों और भाषणों में किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर किसान अपमान और अव्यवस्था झेल रहा है। प्रदेशभर की मंडियों और खरीदी केंद्रों पर भारी अव्यवस्था है, लेकिन सरकार किसानों की समस्याओं को सुनने तक को तैयार नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसान अपना गेहूं कहां बेचें। जब पोर्टल बंद है, स्लॉट नहीं मिल रहा और खरीदी केंद्रों पर सुनवाई नहीं हो रही, तो किसानों को मजबूर होकर अपनी उपज औने पौने दामों में व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की नहीं, बल्कि केवल प्रचार और पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है। यदि जल्द ही खरीदी व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में किसानों के साथ बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी।

पीएचई एसडीओ पर राजधानी के अफसरों की बरस रही मेहरबानी

» कार्यपालन यंत्री समेत दिये गये है चार प्रभार
» सीधी में तीन एवं सिंगरौली जिले का मिला एक प्रभार

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के एसडीओ पर प्रदेश की राजधानी भोपाल से मेहरबानी बरसने से नियम कायदे हासिये पर चले गये हैं। सीधी जिले में यह विभाग गर्मी के दिनों में भगवान भरोसे चल रहा है। यह स्थिति विभाग के बड़े अधिकारियों द्वारा जानबूझकर निर्मित की गई है। दरअसल पीएचई मैकेनिकल एसडीओ सीधी त्रियाम्बकेश द्विवेदी को ईई पीएचई समेत चार प्रभार सौंपे जाने के बाद से व्यवस्थाएं पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। ईई के प्रभार के साथ इन्हें एसडीओ मझौली एवं सिंगरौली में मैकेनिकल इंजीनियर का प्रभार भी सौंपा गया है। वर्तमान में पीएचई विभाग सीधी के अंतर्गत करोड़ों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों की जिम्मेदारी विभागीय सिविल इंजीनियर को सौंपी जानी चाहिए। जिसको निर्माण कार्य के संबंध में पूरी टेक्निकल जानकारी हो। बावजूद इसके मैकेनिकल एसडीओ को सिविल से संबंधित बड़े कार्यों की निगरानी एवं निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभागीय हल्कों में भी यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक साथ चार प्रभार मिलने के कारण श्री द्विवेदी की स्वेच्छाचारिता चरम पर पहुंच चुकी है। इस वजह से विभागीय कार्य भी संबंधित क्षेत्र के उपयंत्रियों की देखरेख में काम चलाऊ कार्य चल रहे हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना के तहत पीएचई विभाग के जिम्मे करोड़ों के कार्य चल रहे हैं। ठेकेदारों के हवाले से अधिकांश कार्य पूर्व से ही कराए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पीएचई विभाग के कार्यों की क्या स्थिति है इसे मौके पर जाकर बाखुबी देखा जा सकता है। ठेकेदारों द्वारा कमीशन के बलबूते आधे-अधूरे कार्य करके छोंड़ दिए गए हैं। जिसके चलते संबंधित क्षेत्रों में नल के माध्यम से पानी आने की योजना एक पहेली बनकर रह गई है।

अजय सिंह ने किया "ज्ञान स्टील इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड" का शुभारंभ

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। चुरहट विधायक एवं मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने जेल रोड पड़रा स्थित "ज्ञान स्टील इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड" का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी बृजेंद्र मिश्रा उपस्थित रहे। इस अवसर पर अजय सिंह ने कहा कि ज्ञान सिंह ने व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है तथा निर्माण क्षेत्र में कदम रखना जिले के विकास और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस उद्योग से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और लोगों को निर्माण सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेगी। कार्यक्रम में ज्ञान सिंह के सामाजिक कार्यों की भी सराहना की गई। वहीं उद्घाटन समारोह के दौरान जिले के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, व्यापारी एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

रिश्वत लेते धरा गया थानाधिकारीः कार से 2.87 लाख रुपए बरामद

लोकतंत्र की शान

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की डूंगरपुर टीम ने प्रतापगढ़ जिले में कार्रवाई करते हुए धोलापानी थाने के थानाधिकारी को रिश्वत प्रकरण में डिटेन किया है। एसीबी टीम ने आरोपित पुलिस निरीक्षक की निजी कार से 2 लाख 87 हजार 150 रुपए की रिश्वत राशि बरामद की है। आरोपित रकम के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। एसीबी महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी डूंगरपुर को शिकायत मिली थी कि परिवादी के भाई के खिलाफ धोलापानी थाने में दर्ज बलात्कार के मामले में मदद करने, मारपीट नहीं करने तथा परिवादी के पिता को मामले में नहीं फंसाने की एवज में थाना अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई की गई। एसीबी उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में एसीबी डूंगरपुर इकाई के पुलिस उप अधीक्षक रतनसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी के अनुसार थाना अधिकारी प्रवीण कुमार चारण रिश्वत राशि परिवादी के परिचित से लेकर निजी वाहन से यात्रा कर रहा था। इस दौरान निम्बाहेड़ा हाईवे स्थित नरसिंहपुरा टोल नाके पर एसीबी की टीम वाहन को रुकवाकर जांच की गई। तलाशी में वाहन से 2.87 लाख रुपए बरामद हुए। रकम के संबंध में आरोपित पुलिस निरीक्षक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। जिस पर उसे डिटेन कर लिया गया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ जारी है।

खाद्यान्न गबन की जांच में लीपापोती, आदेश बेअसर

» खण्ड अधिकारी के नेतृत्व में टीम को करना था जांच
» नेबूहा कैंप में चार वर्ष पूर्व हुए 67 लाख के खाद्यान्न गबन का मामला

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। 67 लाख रुपए के खाद्यान्न गबन मामले की जांच कब पूरी होगी यह अबूझ पहेली बनी हुई है। तत्कालीन कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देश पर पिछले साल जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अपर कलेक्टर के पास जमा कर दिए गए थे। कहा गया था कि जल्द ही उप खण्ड स्तरीय अधिकारी के मार्गदर्शन में जांच टीम का गठन कर नए सिरे से इस भ्रष्टाचार में शामिल सभी जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की करतूतों का खुलासा होगा। लेकिन यह जांच फाइलों में ही कैद होकर रह गई। उल्लेखनीय है कि जिले के मझौली ब्लाक अंतर्गत संचालित नेबूहा कैंप में करीब चार वर्ष पूर्व हुए खाद्यान्न गबन के मामले को मीडिया द्वारा उजागर किए जाने पर तत्कालीन कलेक्टर ने दस्तावेज तलब कर लिया था। जिसकी जांच एवं छानवीन की कार्यवाही शुरू हुई थी। विभाग द्वारा प्रस्तुत किए दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत टीम द्वारा मौके से एवं विभाग के सूत्रों से इस पूरे गोलमाल की जानकारी जुटाना शुरू किया गया था। इस पूरे गबन मामले में तत्कालीन नान प्रबंधक, गोदाम प्रभारी एवं खाद्य अधिकारी की भी संदिग्ध भूमिका थी, जिसके खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित नही की गई है। वहीं विभागीय सूत्रों की मानें तो इस पूरे गबन मामले में मझौली वेयर हाउस प्रबंधक, नेबुहा कैंप प्रभारी, जिला प्रबंधक नान एवं ट्रांसपोर्टर सहित खाद्य विभाग की अहम भूमिका बताई जा रही है। अगर निष्पक्षता पूर्ण इस मामले की जांच हुई तो इस पूरे गोलमाल में शामिल कई चेहरे बेनकाब हो सकते है।

संक्षिप्त समाचार

नेपाल में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नहीं देंगे जवाब, वित्त मंत्री को दी जिम्मेदारी

काठमांडू। नेपाल की संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देने से प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने इंकार कर दिया है और अब प्रधानमंत्री शाह की जगह वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले सरकार की तरफ से जवाब देंगे। प्रतिनिधि सभा की आज की कार्यसूची में भी यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण और सरकार की नीति तथा कार्यक्रम पर उठे सवालों का उत्तर वित्त मंत्री देंगे। आज सुबह तय की गई प्रतिनिधि सभा की दैनिक कार्यसूची के दूसरे नंबर पर यह विषय रखा गया है। कार्यसूची में कहा गया है, "प्रधानमंत्री की ओर से वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा सोमवार को संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए संबोधन में उल्लिखित आर्थिक वर्ष २०२६-२०२७ की नेपाल सरकार की वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पर हुई चर्चा के दौरान उठाए गए प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।" नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा और जवाब के लिए विपक्षी दल प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की उपस्थिति की मांग कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा की बुधवार की बैठक में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति के बाद विपक्षी दलों ने लगातार नारेबाजी और अवरोध किया था। विपक्ष का कहना था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव स्वयं प्रधानमंत्री को सदन में पेश करना चाहिए। बाद में अध्यक्ष डीपी आर्यल की पहल पर हुई चर्चा के बाद विपक्षी दल मंत्रियों को प्रस्ताव टेबल करने देने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने चर्चा और जवाब के दौरान प्रधानमंत्री की उपस्थिति अनिवार्य होने की बात पर अड़े रहे। विपक्षी दलों ने कई बार स्पीकर से प्रधानमंत्री को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्यवस्था देने की मांग की थी। हालांकि, अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की कार्यसूची की जानकारी अपने पास न होने की बात कहते हुए ऐसा निर्णय देने में असमर्थता जताई। इसके बाद विपक्ष ने कल सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। विपक्ष के लगातार अवरोध के बाद अध्यक्ष ने बैठक को आज तक के लिए स्थगित कर दिया था। अब आज की बैठक में नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा होने की कार्यसूची तय की गई है। वित्त मंत्री के जवाब देने के बाद सरकार की वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पर प्राप्त संशोधनों को निर्णय के लिए पेश किया जाएगा। आज ही सरकार की वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम को निर्णयार्थ प्रस्तुत करने की भी कार्यसूची है। इसके बाद विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताएं पेश की जाएंगी।

रूस ने यूक्रेन पर किया ड्रोन और मिसाइल हमला, 14 की मौत

कीव (यूक्रेन)। रूस ने पूरे यूक्रेन में बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया है। रूस ने बुधवार सुबह से आधीरात बाद तक ताबड़तोड़ हमला कर तबाही मचा दी। इन हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक नागरिक घायल हो गए। राजधानी कीव में रूस के हमले से एक आवासीय इमारत ढह गई। इस इमारत के मलबे में दबे 10 लोगों को बचाया गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। रात लगभग एक बजे यूक्रेन की वायुसेना ने देशव्यापी हवाई अलर्ट जारी किया। इसमें चेतावनी दी गई कि रूस ने मिग-31 बमवर्षक विमानों को तैनात कर दिया है। देश का हर क्षेत्र बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की जद में है। द कीव इंडिपेंडेंट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, कीव सैन्य प्रशासन के प्रमुख टिमुर टकाचेंको ने कुछ देर बाद चेतावनी दी क रूसी ड्रोन राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं और मिसाइल हमले भी संभावित खतरा हैं। स्थानीय समयानुसार तड़के 3:08 बजे कीव में जोरदार धमाके हुए। यूक्रेन की हवाई रक्षा प्रणालियां रूसी ड्रोन से जूझती नजर आईं।3:15 बजे से 3:20 बजे के बीच बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से होने वाले धमाकों की आवाज सुनी गई। इसके कुछ देरबाद लगभग 3:44 बजे फिर बैलिस्टिक मिसाइलों ने गरजना शुरू कर दिया। कीव के मेयर विटाली क्लिट्को ने बताया कि गिरे हुए ड्रोन के मलबे से निप्रोव्स्की जिले में एक पांचमंजिला आवासीय इमारत की छत पर आग लग गई और होलोसीव्स्की जिले में एक सड़क पर मलबा गिर गया। ड्रोन का मलबा एक कार्यालय की इमारत और एक पार्किंग संरचना पर गिरा। ओबोलोन्स्की जिले में एक 12 मंजिला आवासीय इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरने के बाद उसमें आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि एक निर्माणाधीन 25 मंजिला इमारत पर भी हमला किया गया सोलोम्यांस्की जिले में रूसी ड्रोन के मलबे से एक कार में आग लग गई। रूस की सेना ने 13 मई की दोपहर यूक्रेन के जरूरी और आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हमला किया। इस हमले के कई चरणों में कम से कम 800 ड्रोन से कई शहरों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए। इसके बाद रूस ने आधीरात बाद फिर हमले किए। रूस के ड्रोन हमलों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस मिसाइल हमले भी कर सकता है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी एचयूआर ने पहले ही राष्ट्रपति को आगाह किया था कि रूसी सेना बड़ी संख्या में हवा और समुद्र से छोड़ी जाने वाली क्रूज मिसाइलों, साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले जारी रखने की योजना बना रही है।

रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के पूर्व अधिकारियों के आवासों पर सीबीआई की छापेमारी

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एडीए समूह की कंपनियों में से एक 'रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड' के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में गुरुवार को 7 परिसरों पर तलाशी ली। ये परिसर तीन शहरों मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित हैं। कंपनी के तत्कालीन सीईओ, सीएफओ और निदेशकों के आवासीय परिसरों पर यह तलाशी की गई। इन्होंने 2015-2017 के दौरान अपनी सेवाएं दीं। यह तलाशी मुंबई के सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश के आज जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और आगे की जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के खिलाफ विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा दर्ज शिकायतों के आधार पर हजारों करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी के संबंध में सात मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में कथित नुकसान की कुल राशि 27,337 करोड़ रुपये है। इन मामलों के दर्ज होने के बाद सीबीआई ने पिछले कुछ महीनों में 31 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। रिलायंस कम्युनिकेशंस के संयुक्त अध्यक्ष डी. विश्वनाथ और उपाध्यक्ष अनिल कालिया को 20 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से संबंधित मामलों की जांच की निगरानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है।

चारधाम यात्रा में 25 दिनों में 40 श्रद्धालुओं की मौत

देहरादून। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड बना रही है। 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में 13 मई तक 12 लाख 64 हजार 217 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर यात्रा के दौरान मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) की 14 मई सुबह 10 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक चारधाम यात्रा में 40 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 22 मौतें केदारनाथ धाम में दर्ज की गई हैं। वहीं बद्रीनाथ में 7, यमुनोत्री में 6 और गंगोत्री में 5 श्रद्धालुओं की जान गई है। सरकार लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल तैयारियों का दावा कर रही है, लेकिन लगातार बढ़ते मौत के आंकड़े यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य चुनौतियों और हाई एल्टीट्यूड से जुड़ी परेशानियों की गंभीरता भी दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अधिकांश मौतें हार्ट अटैक, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, हाइपरटेंशन और अन्य स्वास्थ्य कारणों से हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चारधाम यात्रा में अब तक हुई अधिकांश मौतें स्वास्थ्य खराब होने, हार्ट अटैक और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसी समस्याओं के कारण हुई हैं। यात्रा मार्ग ऊंचाई वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जहां ऑक्सीजन का स्तर कम होने और लगातार चढ़ाई की वजह से बुजुर्गों और पहले से बीमार यात्रियों की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार ने कई समीक्षा बैठकें की थीं। सभी विभागों को यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। सरकार का दावा है कि यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

नीट पेपर लीक, शिक्षा मंत्री को अहमदाबाद में काले झंडे दिखाए

राजस्थान पुलिस बोली- गेस पेपर 1000 छात्रों तक पहुंचा, अब तक 5 गिरफ्तार

एजेंसी, पुणे/गुरुग्राम/जयपुर/अहमदाबाद

NEET पेपर लीक पर देशभर में विरोध के बीच अहमदाबाद में NSUI कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाए और काफिला रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। CBI ने मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले बुधवार को 14 संदिग्धों से 24 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी। आरोपियों को बुधवार को कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया था। अब CBI सभी आरोपियों को दिल्ली ले जाएगी। राजस्थान के सीकर से आरोपी मांगी लाल बिंवाल, जमवारामगढ़ के भाई दिनेश बिंवाल, बेटा विकास बिंवाल, हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक से शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया है। शुभम ने ही यश को पेपर दिया था। जांच एजेंसी ने विक्रम यादव, योगेश प्रजापत, संदीप हरितवाल, नीतेश अजमेरा, सत्यनारायण, विक्रम, राकेश, रजत, अमित मीणा और रोहित मावलिया को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के पुणे से ब्यूटीशियन मनीषा वाघमारे है और अहिल्यानगर से धनंजय निवृत्ति लोखंडे (26) को भी हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि मनीषा के 21 खातों में 10 लाख रुपए जमा किए गए थे।

NEET फर्जीवाड़ाः RJD के राष्ट्रीय सचिव, डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तारः NEET पेपर लीक के बाद एग्जाम कैंसिल कर दिया है। जांच सीबीआई को दी गई है। इधर, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर दिल्ली पुलिस ने एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जो NEET अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को MBBS में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी करता था। इस मामले में सरगना और एक डॉक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार चार आरोपियों में से एक राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल भी हैं। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जायसवाल पूरे नेक्सस का किंगपिन है। ये बच्चों और उनके गार्जियन को मेडिकल कॉलेज में 20-30 लाख में एडमिशन कराने का झांसा देता था। संतोष कुमार जायसवाल को लालू यादव और तेजस्वी यादव का करीबी बताया जाता है।

जमीन कब्जा और रंगदारी मामले में ईडी के सामने पेश हुए कोलकाता पुलिस के डीसीपी

एजेंसी, कोलकाता

♦ हाल में जारी किए गए नए समन के बावजूद वह एजेंसी के सामने पेश होने से बच रहे थे

पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास गुरुवार को जमीन कब्जा और रंगदारी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। ईडी के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। शांतनु सिन्हा बिस्वास पहले कालीघाट थाने के प्रभारी रह चुके हैं और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। ईडी ने उन्हें इससे पहले भी कई बार तलब किया था, लेकिन वह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। बताया गया है कि हाल में जारी किए गए नए समन के बावजूद वह एजेंसी के सामने पेश होने से बच रहे थे। इसके बाद बुधवार को ईडी ने सुरक्षा निदेशालय को पत्र लिखकर उनके ठिकाने की जानकारी मांगी थी। ईडी अधिकारी के अनुसार, बिस्वास को 28 अप्रैल को भी पेश होने के लिए कहा गया था, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले की तारीख थी, लेकिन वह उस दिन भी उपस्थित नहीं हुए।

इसके बाद ईडी ने उनके देश छोड़कर जाने की आशंका को देखते हुए लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। यह सर्कुलर हवाई अड्डों और सीमा सुरक्षा बल की चौकियों तक भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक, गोलपार्क इलाके के कारोबारी 'सोना पप्पू' से जुड़े जमीन कब्जा, रंगदारी और अन्य मामलों की जांच के दौरान शांतनु सिन्हा बिस्वास का नाम सामने आया था। ईडी को बेहाला के कारोबारी जॉय कामदार की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तारी के बाद भी बिस्वास के खिलाफ कुछ अतिरिक्त जानकारियां मिली हैं। एजेंसी लंबे समय से उनसे पूछताछ करने का प्रयास कर रही थी।

फाजिल्का बॉर्डर पर मिला पाकिस्तानी ड्रोन, हेरोइन तस्करी की आशंका

एजेंसी, चंडीगढ़

पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए नशा और हथियार तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन सीमा पार से ड्रोन गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार देर रात फाजिल्का के भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया।

पुलिस के अनुसार गांव चक्क बाजीदा के खेतों में ड्रोन गिरने की सूचना मिलने के बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान खेतों से एक ड्रोन बरामद किया गया। इस मामले में थाना सदर जलालाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस चौकी घुबाया के इंचार्ज गुरनाम सिंह ने बताया कि बीएसएफ से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। उन्होंने बताया कि एक किसान के खेत में गेहूं के नाड़ के बीच ड्रोन पड़ा मिला, जिसे कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि यह ड्रोन सीमा पार से हेरोइन की खेप गिराने के बाद वापस लौट रहा था, लेकिन बैटरी खत्म होने या किसी तकनीकी खराबी के कारण खेतों में गिर गया। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्रोन किसके लिए भेजा गया था।

मप्र के देवास में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, तीन की मौत, 25 मजदूर घायल

एजेंसी, देवास

मध्य प्रदेश के देवास जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम टोंककला के समीप स्थित एक पटाखा फैक्टरी में गुरुवार को जोरदार विस्फोट होने के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में तीन श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 25 घायल हैं। घटना के बाद प्रशासन ने फैक्टरी को सील कर दिया है, जबकि पुलिस ने फैक्टरी मालिक अनिल मालवीय को हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया और घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ग्राम टोंककला स्थित पटाखा फैक्टरी में गुरुवार सुबह करीब 10.30 बजे दो केमिकल मिलाकर बारूद बनाया जा रहा था। इसी दौरान केमिकल की मात्रा सही नहीं मिलने से विस्फोट हो गया। इसके बाद फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी, जिससे अंदर मौजूद मजदूरों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राहत-बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए और घायलों को तत्काल एंबुलेंस और अन्य वाहनों से जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

जिला प्रशासन ने हादसे में तीन श्रमिकों की मौत की पुष्टि की है। मृतकों के नाम धीरज, सनी और सुमित बताए गए हैं। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों को इंदौर के टी. चोइथराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं तीन घायलों का उपचार एमवाय अस्पताल में चल रहा है, जबकि कुछ मरीजों को अरविंदो अस्पताल रेफर किया गया है। इसके अलावा लगभग नौ घायल देवास के अमलतास अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों में पांच की स्थिति नाजुक बताई जा रही है।

हादसे के बाद फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य और केमिकल के सैंपल एकत्र किए, जिनकी जांच की जा रही है। मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ डॉ. रश्मि भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर तकनीकी पहलुओं की जानकारी जुटाई। फिलहाल पूरे मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच जारी है। घटना के बाद प्रशासन ने पटाखा फैक्टरी को सील कर दिया है। मौके पर पुलिस फोर्स और जांच टीम तैनात है। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने बताया कि यह फैक्टरी अनिल मालवीय नाम के व्यक्ति की है। यहां करीब 15 दिन पहले ही छोटे पटाखे बनाने का काम शुरू किया गया था और फैक्टरी के नाम लाइसेंस भी जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि फैक्टरी में हुए हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल : आसनसोल के कोयला खदान में एयर ब्लास्ट, 40 से ज्यादा श्रमिक घायल

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल के आसनसोल में इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) के कुनुस्तोरिया क्षेत्र स्थित पड़ाशिया (परशिया) कोलियरी की भूमिगत खदान में हुए भयावह एयर ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 40 से अधिक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि एक श्रमिक की मौत हो गई है। हालांकि, खदान प्रबंधन की ओर से खबर लिखे जाने तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह पहली शिफ्ट के दौरान करीब 10:30 बजे खदान के 27 नंबर विभाग में श्रमिक कोयला कटाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक खदान की एक परत से तेज एयर ब्लास्ट हुआ, जिससे भीतर जबरदस्त वायु दबाव बन गया। विस्फोट से श्रमिक दूर जा गिरे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उस समय उक्त खदान में करीब 20-25 कर्मचारी मौजूद थे, जिनमें दो अधिकारी भी शामिल थे।

बता दें कि, खदान में एयर ब्लास्ट एक अत्यंत खतरनाक घटना है, जो मुख्य रूप से भूमिगत कोयला खदानों में छत गिरने के कारण उत्पन्न होती है। इसमें खदान की खाली जगह में फंसी हवा अचानक भारी दबाव के साथ बाहर निकलती है, जो खनिकों को घायल या मृत कर सकती है और मशीनरी को तबाह कर सकती है। प्रत्यक्षदर्शी श्रमिक राकेश कुर्मी ने बताया कि करीब 10:30 बजे अचानक जोरदार धमाका महसूस हुआ। देखते ही देखते तेज हवा का दबाव बना और वहां मौजूद सभी लोग गिर पड़े। कुछ समझ पाते, उससे पहले ही पूरा क्षेत्र धूल और धुएं से भर गया। उस समय करीब 20-25 लोग वहां काम कर रहे थे, जिनमें दो अधिकारी भी थे। हादसे से खदान के अंदर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पाकर मौजूद अधिकारियों और बचाव दल ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर रानीगंज के बांसड़ा एरिया अस्पताल, ईसीएल के अन्य अस्पतालों तथा दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, कई घायलों की हालत गंभीर है। घायलों में कई ठेका मजदूरों के साथ-साथ कोलियरी के अतिरिक्त प्रबंधक दिलीप कुमार भी घायल हुए हैं। इस घटना के बाद खदान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

दिल्ली- लाल किला ब्लास्ट मामले में 7500 पेज की चार्जशीट

एजेंसी, नई दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने वाले कार बम धमाके मामले में NIA ने 7500 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित NIA स्पेशल कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में 10 आरोपियों को नामजद किया गया है।

10 नवंबर, 2025 की शाम लाल किले के पास हुए इस धमाके में 11 लोगों की मौत, जबकि कई घायल हुए थे। NIA की जांच में पता चला है कि सभी आरोपी आतंकी संगठन सार गजवत-उल-हिंद और अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) से जुड़े थे। गिरफ्तार किए गए 8 आतंकियों में 5 पेशे से डॉक्टर हैं। चार्जशीट में मुख्य आरोपी पुलवामा निवासी डॉ. उमर उन नबी का भी नाम है, जिसकी मौत हो चुकी है। वह हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका था। NIA की जांच में सामने आया कि कुछ आरोपी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित मेडिकल प्रोफेशनल थे। 2022 में श्रीनगर में हुई एक गुप्त बैठक में उन्होंने "AGuH Interim" नाम से संगठन को फिर सक्रिय किया और "Operation Heavenly Hind" शुरू किया था। आरोपियों ने नए सदस्यों की भर्ती और बड़े पैमाने पर विस्फोटक तैयार किया था। एजेंसी ने बताया कि धमाके में इस्तेमाल TATP विस्फोटक आरोपियों ने खुद तैयार किया था। इसके लिए केमिकल और उपकरण ऑनलाइन व ऑफलाइन जुटाए गए थे।

अखिलेश के भाई प्रतीक को ससुर ने दी मुखाग्नि

एजेंसी, लखनऊ

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक गुरुवार दोपहर पंचतत्व में विलीन हो गए। लखनऊ में पत्नी अपर्णा के पिता यानी प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने चिता को मुखाग्नि दी। अखिलेश ने भाई की चिता पर लकड़ी रखी और अंतिम प्रणाम किया। प्रतीक की दोनों बेटियां प्रथमा और पद्मजा भी श्मशान घाट पर मौजूद रहीं। दोनों ने पिता की चिता पर लकड़ी रखी। प्रतीक की छोटी बेटी पद्मजा अपने ताऊ अखिलेश के पास थी। अखिलेश ने उससे बात की और चॉकलेट खिलाई। अंतिम संस्कार कराने वाले पंडित ध्रुव कुमार तिवारी ने दैनिक भास्कर से कहा था- अगर अखिलेश यादव या उनके बेटे से मुखाग्नि दिलाई जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे पहले, प्रतीक की अंतिम यात्रा निकाली गई। शिवपाल के बेटे आदित्य ने शव को कंधा दिया। प्रतीक एनिमल लवर थे। शव वाहन पर उनकी डॉग्स और बंदर के साथ वाली तस्वीर लगाई गई। प्रतीक का बुधवार सुबह 6 बजे 38 साल की उम्र में निधन हुआ था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डिएक अरेस्ट बताई गई। उनके शरीर पर 6 चोटें पाई गईं, जो मौत से पहले लगी थीं। इनमें 3 चोटें 7 दिन पुरानी और 3 चोटें एक दिन पुरानी थीं। उनका विसरा सुरक्षित रखा गया है। प्रतीक, मुलायम यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा नेता हैं। इस वक्त राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं।

बंगाल सरकार ने स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल की BJP सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की असेंबली में 'वन्दे मातरम' को अनिवार्य कर दिया है। सभी स्टूटेंट्स को इसमें शामिल होना पड़ेगा। वहीं, सरकार गोहत्या से जुड़े 1950 के कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि बिना 'फिटनेस सर्टिफिकेट' के किसी भी मवेशी-भैंस की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंध है। बंगाल सरकार ने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट केवल किसी नगरपालिका के अध्यक्ष, किसी पंचायत समिति के प्रमुख और एक सरकारी पशु चिकित्सक के साथ मिलकर जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट तभी जारी होगा जब अथॉरिटी सहमत हो कि जानवर 14 साल से ज्यादा उम्र का है, वह प्रजनन के लायक नहीं और बूढ़ा है। चोटिल और अपंग है, या लाइलाज बीमारी के कारण अक्षम है। इसके अलावा सार्वजनिक बूचड़खानों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि जानवरों की हत्या केवल नगरपालिका के बूचड़खाने, या स्थानीय प्रशासन से निर्धारित बूचड़खाने में ही की जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिन के भीतर यह जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी।

हावड़ा के नाबन्ना में नवनिर्वाचित BJP सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। CM अधिकारी ने कहा कि यह फैसला बैठक में लिए गए मुख्य प्रस्तावों में से एक था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि TMC सरकार ने राज्य में पुराने IPC और CrPC की जगह नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) को लागू नहीं किया था। राज्य में अब BNS लागू करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना भी पश्चिम बंगाल में भी लागू की जाएंगी।

बांग्लादेश से लगती है बंगाल की 2216 किमी सीमाः भारत, बांग्लादेश के साथ 4,097 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार लगभग 3,240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है और लगभग 850 किलोमीटर, जिसमें 175 किलोमीटर का दुर्गम भूभाग भी शामिल है, इस पर बाड़बंदी होनी बाकी है। CM अधिकारी ने दावा किया कि प्रस्तावित 127 किलोमीटर के खंड में से केवल लगभग 8 किलोमीटर के हिस्से को ही ममता बनर्जी की सरकार के कार्यकाल में फेंसिंग की गई थी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2,216 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। यह भारत-बांग्लादेश की सबसे लंबी स्टेट बॉर्डर है। 2021 में केंद्र सरकार ने बंगाल में बॉर्डर पर BSF के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया था। यानी BSF 50km तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कर सकती है। तत्कालीन ममता सरकार ने इसे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप बताया था। दिसंबर 2021 में बंगाल विधानसभा में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया था।

ड्रैगन लैंड में ट्रंप-दिल में तेहरान :ताइवान पर कोहराम- महाशक्ति की महापंचायत- मिशन तेहरान,कुर्बान ताइवान गहरा तनाव का समग्र व्यापक विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» आधुनिक विश्व राजनीति में आदर्शवाद से अधिक महत्व राष्ट्रीय हितों का -हर देश क़ा अपने आर्थिक,सामरिक और राजनीतिक हितों के आधार पर निर्णय लेना राष्ट्रवाद

» ट्रंप का चीन दौरा -एक तरफ तेहरान का संकट, दूसरी तरफ ताइवान का विस्फोटक प्रश्न, दोनों के बीच खड़ी पूरी दुनियाँ ?क्या महाशक्तियाँ प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित कर पाएंगी या दुनियाँ नए शीत युद्ध और बड़े संघर्षों की ओर बढ़ेगी? -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर 13 से 15 मई 2026 तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की चीन यात्रा केवल एक औपचारिक राजकीय दौरा नहीं,बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति, डगमगाती अर्थव्यवस्था,पश्चिम एशिया के युद्ध, ताइवान संकट और महाशक्तियों की नई रणनीतिक शतरंज का ऐसा मंच बन गई, जिसपर पूरी दुनियाँ की निगाहें टिक गईं। लगभग नौ वर्षों बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की यह बड़ी आधिकारिक चीन यात्रा ऐसे समय में हुई,जब वैश्विक व्यवस्था कई मोर्चों पर अस्थिरता से गुजर रही है।एक तरफ पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट विश्व अर्थव्यवस्था की धड़कनें बढ़ा रहा है,तो दूसरी ओर हिंद- प्रशांत क्षेत्र में ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आमने- सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। बीजिंग में हुई ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति क्षी जिनपिंग की मुलाकात ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि दुनियाँ अब केवल सैन्य शक्ति से नहीं,बल्कि आर्थिक गठबंधनों, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और सामरिक दबावों से संचालित होने वाली नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र इस शिखर वार्ता को मानता हूं कि यह एकऐसी महाशक्तियों की महापंचायत हैं,जहाँ बाहर मुस्कुराहटें थीं लेकिन भीतर तेहरान और ताइवान को लेकर गहरा तनाव मौजूद था। साथियों, ट्रंप का यह दौरा ऐसे समय पर हुआ, जब अमेरिका और चीन के संबंध पिछले कई वर्षों से व्यापार युद्ध, तकनीकी प्रतिबंधों,चिप उद्योग की प्रतिस्पर्धा दक्षिण चीन सागर विवाद और ताइवान प्रश्न को लेकर लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं।हालांकि सार्वजनिक मंचों पर दोनों देशों ने संवाद और स्थिरता की भाषा अपनाई, लेकिन वास्तविकता यह रही कि दोनों महाशक्तियाँ अपनी - अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ वार्ता टेबल पर पहुँची थीं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध को नियंत्रित करना, होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलना और वैश्विक सप्लाई चेन को स्थिर करना था, जबकि चीन के लिए ताइवान उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न बना हुआ है। इसीलिए बीजिंग की बैठक में जब शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि ताइवान चीन-अमेरिका संबंधों का सबसे संवेदनशील मुद्दा है, तब यह केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि सीधी रणनीतिक चेतावनी थी।यह यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की यह पहली चीन यात्रा थी। इससे पहले वे 2017 में चीन गए थे। तब वैश्विक परिदृश्य अलग था, लेकिन अब दुनिया बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है। 2025 में दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, परंतु बीजिंग की यह बैठक कहीं अधिक निर्णायक मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस बार अकेले नहीं पहुँचे थे। उनके साथ दुनिया की सबसे प्रभावशाली तकनीकी और कॉरपोरेट हस्तियाँ भी थीं, जिनमें एलोंन मुस्क , टिम कुक और जिनसेन हुग जैसे नाम शामिल थे। यह संकेत था कि यह यात्रा केवल भू- राजनीति तक सीमित नहीं है,बल्कि इसके केंद्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीकी वर्चस्व और बाजारों की पुनर्संरचना भी सटीकता से शामिल है। साथियों, दरअसल,वर्तमान समय में अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा केवल सैन्य शक्ति की नहीं,बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डेटा, 5जी नेटवर्क और वैश्विक सप्लाई चेन के नियंत्रण की लड़ाई बन चुकी है। अमेरिका चीन पर तकनीकी निर्भरता कम करना चाहता है, जबकि चीन पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद तकनीकीआत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रंप के साथ शीर्ष अमेरिकी टेक कंपनियों के प्रमुखों का बीजिंग पहुँचना यह दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद व्यावसायिक हित अभी भी संवाद का सबसे बड़ा पुल बने हुए हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है और अमेरिकी कंपनियाँ वहाँ अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहती हैं। वहीं चीन अमेरिकी निवेश, तकनीक और बाजार पहुँच को पूरी तरह खोना नहीं चाहता। लेकिन इस पूरी यात्रा के केंद्र में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान संकट बनकर उभरा। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहाँ से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है, युद्ध की स्थिति के कारण गंभीर तनाव में है। भारत सहित एशिया के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति इसी मार्ग पर निर्भर करती है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है और उसका बड़ा भाग होर्मुज से होकर आता है। युद्ध और समुद्री तनाव के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था, रुपये की स्थिति और महंगाई पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया यह देख रही थी कि क्या ट्रंप चीन के माध्यम से ईरान पर दबाव बनाने की सटीकता से कोशिश करेंगे। साथियों, चीन ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदारों में से एक है। चीन ईरानी तेल का प्रमुख खरीदार है और पश्चिम एशिया में उसकी रणनीतिक उपस्थिति लगातार बढ़ी है। यही कारण है कि अमेरिका अब चीन की सहायता चाहता दिखाई दे रहा है, ताकि तेहरान को वार्ता की मेज पर वापस लाया जा सके। कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की बीजिंग यात्रा का वास्तविक "मिशन तेहरान" ही था। अमेरिका समझता है कि केवल सैन्य दबाव से ईरान को झुकाना कठिन होगा। यदि चीन चाहे तो वह आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव के माध्यम से ईरान को बातचीत के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए यह यात्रा मिशन तेहरान, कुर्बान ताइवान जैसी बहसों को जन्म दे रही है, जहाँ सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान संकट के समाधान के बदले ताइवान परअपेक्षाकृत नरम रुख अपना सकता है।हालांकि चीन ने भी इस मौके का पूरा रणनीतिक उपयोग किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्वयं ट्रंप को रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं गए। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में इस प्रकार के संकेतों को बेहद गंभीरता से देखा जाता है। इससे यह संदेश गया कि चीन अमेरिका से संवाद तो चाहता है, लेकिन बराबरी की स्थिति में। चीन ने स्पष्ट कर दिया कि ताइवान पर उसकी रेड लाइन कायम है। जिनपिंग ने साफ कहा कि ताइवान चीन का आंतरिक मामला है और यदि इस मुद्दे को गलत तरीके से संभाला गया तो दोनों देशों के बीच सीधा टकराव हो सकता है। यह बयान केवल अमेरिका के लिए नहीं था, बल्कि ताइवान और उसके समर्थक देशों के लिए भी था। साथियों, ताइवान ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ताइवान सरकार के प्रवक्ताओं ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में असुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत चीन की सैन्य आक्रामकता है। ताइवान लगातार अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने और अमेरिका सहित सहयोगी देशों के साथ सामरिक साझेदारी मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियाँ तेज की हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। अमेरिका ताइवान को हथियार सहायता देता रहा है, जबकि चीन इसे अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप मानता है। यही कारण है कि बीजिंग वार्ता में ताइवान सबसे संवेदनशील मुद्दा बनकर सामने आया। साथियों, दिलचस्प बात यह रही कि ट्रंप ने ताइवान को लेकर सीधे जवाब देने से बचने की कोशिश की। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या जिनपिंग के साथ ताइवान पर चर्चा हुई, तो उन्होंने विषय बदल दिया और चीन की सुंदरता की बात करने लगे।इसे कई विशेषज्ञरणनीतिक चुप्पी मान रहे हैं। संभव है कि ट्रंप इस समय ईरान और वैश्विक व्यापार संकट को प्राथमिकता दे रहे हों और ताइवान पर खुलकर बयान देकर चीन को नाराज नहीं करना चाहते हों। यही वजह है कि दुनिया भर में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या अमेरिका किसी बड़े सामरिक समझौते की ओर बढ़ रहा है।इस यात्रा का आर्थिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है।अमेरिका चाहता है कि चीन अमेरिकी कृषि उत्पादों, ऊर्जा संसाधनों और बोइंग विमानों की खरीद बढ़ाए। दूसरी ओर चीनअमेरिकी तकनीकी प्रतिबंधों में नरमी चाहता है। ट्रेड वॉर के वर्षों बाद दोनों देशों ने पहली बार खुले तौर पर आर्थिक स्थिरता की बात की। यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिकसमझौते आगे बढ़ते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में कमी, सप्लाई चेन की बहाली और निवेशकों के विश्वास में सुधार से विश्व अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। साथियों, भारत के लिए भी यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत एक तरफ अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, तो दूसरी ओर चीन उसका सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी। यदि अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होता है, तो हिंद-प्रशांत की रणनीतिक राजनीति में नए समीकरण उभर सकते हैं। दूसरी ओर यदि होर्मुज संकट का समाधान निकलता है और तेल कीमतें कम होती हैं, तो भारत को आर्थिक राहत मिलेगी। पेट्रोल- डीजल की कीमतों में स्थिरता, रुपये की मजबूती और आयात बिल में कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल सकारात्मक सटीक संकेत होंगे। साथियों, बीजिंग की इस मुलाकात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। यह दिखाता है कि अमेरिका और चीन अब केवल द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि ऐसी दो महाशक्तियाँ हैं जिनके निर्णय पूरी दुनिया की दिशा तय करते हैं। यदि दोनों के बीच संबंध बिगड़ते हैं तो वैश्विक मंदी, तकनीकी विभाजन और सैन्य तनाव बढ़ सकते हैं। वहीं यदि दोनों सीमित सहयोग का रास्ता चुनते हैं, तो वैश्विक स्थिरता की संभावना बढ़ सकती है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क्रि इस पूरी यात्रा ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक विश्व राजनीति में आदर्शवाद से अधिक महत्व राष्ट्रीय हितों का है। हर देश अपने आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक हितों के आधार पर निर्णय लेता है। अमेरिका ईरान संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहता है। चीन ताइवान पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहता। दोनों देश एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी भी हैं और आवश्यकता पड़ने पर साझेदार भी। यही आज की वैश्विक राजनीति की वास्तविकता है ।बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग की यह मुलाकात केवल दो नेताओं की बैठक नहीं, बल्कि आने वाले दशक की वैश्विक दिशा तय करने वाली घटना बन गई है। एक तरफ ट्रंप की "डील मेकर" राजनीति है, दूसरी तरफ जिनपिंग का राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सपना। एक तरफ तेहरान का संकट है, दूसरी तरफ ताइवान का विस्फोटक प्रश्न। इन दोनों के बीच खड़ी है पूरी दुनिया, जो यह जानना चाहती है कि क्या महाशक्तियाँ प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित कर पाएंगी या फिर आने वाला समय नए शीत युद्ध और बड़े संघर्षों की ओर बढ़ेगा।फिलहाल इतना स्पष्ट है कि ड्रैगन लैंड में हुई यह महाशक्ति महापंचायत केवल वर्तमान की सुर्खी नहीं, बल्कि भविष्य की भू-राजनीतिक पटकथा का प्रारंभिक अध्याय है।

-संकलनकर्ता लेखक
- क़र विशेषज्ञ स्तंभकार
साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक
चिंतक कवि संगीत माध्यमा
सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन
सनमुखदास भावनानीं गोंदिया
महाराष्ट्र 9226229318

भगत सिंह के मस्तिष्क शहीद सुखदेव को हमने कितना याद रखा?

लेखक- दिलीप कुमार पाठक

इतिहास की एक अजीब फितरत होती है। वह कभी-कभी किसी महानायक के महाकाय प्रभाव में उसके सबसे बड़े मददगार और हमसफर को परदे के पीछे धकेल देता है। 23 मार्च 1931 की शाम को जब लाहौर की सेंट्रल जेल में तीन नौजवान फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे, तब भारत की जुबान पर एक नाम ऐसा चढ़ा कि बाकी दो नाम उसके साए में थोड़े सिमट गए। हम बात कर रहे हैं क्रांति के तीन शहीदों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। इस अटूट तिकड़ी में भगत सिंह क्रांति का चमकता हुआ चेहरा थे और राजगुरु अचूक निशानेबाज, लेकिन इन सबके पीछे जो बेहद शांत, गंभीर और तीखा दिमाग काम कर रहा था, वह नाम था क्रांतिकारी सुखदेव थापर का। आज 15 मई को उनकी जयंती पर यह सोचना बहुत जरूरी है कि इस जमीनी रणनीतिकार को हमने अपनी यादों और इतिहास में कितना स्थान दिया। पंजाब के लायलपुर में जन्मे सुखदेव और भगत सिंह सिर्फ साथ में देश के लिए लड़ने वाले साथी नहीं थे, बल्कि दोनों के बीच एक बेहद गहरी और बेमिसाल दोस्ती थी। लाहौर के नेशनल कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ यह साथ देश की आजादी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। जब देश में नौजवानों को एकजुट करने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ, तो पंजाब की पूरी जिम्मेदारी सुखदेव को सौंपी गई। यहीं से उनके संगठन बनाने और उसे चलाने के लाजवाब हुनर की शुरुआत होती है। वे कागजों पर बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें चुपचाप जमीन पर सच कर दिखाने में माहिर थे।अक्सर स्कूल-कॉलेज की किताबों में सुखदेव को भगत सिंह के एक साथी के रूप में ही दिखाकर छोड़ दिया जाता है, जो उनके साथ एक तरह की नाइंसाफी है। असलियत तो यह है कि ब्रिटिश पुलिस ने जब अदालत में मशहूर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा दर्ज किया था, तो उसकी पहली एफआईआर में आरोपी नंबर एक कोई और नहीं, बल्कि खुद सुखदेव थापर थे। अंग्रेज सरकार भी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इस पूरी सशस्त्र क्रांति की डोर असल में किसके हाथ में है। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जब जेपी सांडर्स को सजा देने की योजना बनी, तो उसके पीछे असली दिमाग सुखदेव का ही था। उन्होंने ही राजगुरु और भगत सिंह को इस बड़े मिशन के लिए तैयार किया, उनके छिपने के गुप्त ठिकाने ढूंढे और काम पूरा होने के बाद वहां से सुरक्षित निकलने का पूरा रास्ता साफ किया। सुखदेव कभी वाहवाही लूटने या अखबारों की सुर्खियों में रहने वाले नेता नहीं थे। वे खुद को हमेशा पीछे रखकर संगठन को मजबूत करते रहे, गलियों-कस्बों में जाकर युवाओं के दिलों में आजादी की अलख जगाते रहे। सुखदेव के बारे में इतिहास का एक पन्ना ऐसा भी है जो अमूमन चर्चाओं से गायब रहता है। जेल की कालकोठरी में रहते हुए जब राजनीतिक कैदियों के मानवीय अधिकारों का हनन हुआ, तब सुखदेव ने जेल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने जेल के भीतर बिना अन्न-जल के लगातार 63 दिनों तक ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी। इस कड़े और जानलेवा उपवास ने ब्रिटिश हुकूमत के क्रूर रवैये को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। इस बात से सिद्ध हो जाता है कि वे सिर्फ बम और पिस्तौल की रणनीति ही नहीं जानते थे, बल्कि वैचारिक और सत्याग्रही मोर्चे पर भी उनका कोई सानी नहीं था। उनकी सोच कितनी खुली और साफ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे किसी भी तरह के अंधविश्वास और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे। जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए उन्होंने महात्मा गांधी को एक खुला खत लिखा था, जिसमें उन्होंने देश के युवाओं की दशा पर बेहद कड़े और सीधे सवाल पूछे थे। यह चिट्ठी बताती है कि उनका दिल देश के भविष्य के लिए कितना तड़पता था। लेकिन आजादी मिलने के बाद हमारे देश के नीति-निर्माताओं और इतिहासकारों ने सुखदेव के योगदान को वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हकदार थे।

राजनीतिक नेता मलाई खाएं और मजदूर भूखा रहे; "मजदूर जाए तो जाए कहां"

सैयद इसरार हुसैन

मजदूर वर्ग केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का "आधार स्तंभ" है, लेकिन यह दिन-ब-दिन कमजोर होता दिखाई दे रहा है। सरकार और राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के प्रयास में लगे हैं, परंतु मजदूरों (देश के शिल्पकार) को वेतन, पेंशन, भत्ते और स्वास्थ्य सुविधाएं देने में असमर्थ दिखाई देते हैं। हर वर्ष 1 मई को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। यदि आज दुनिया पर नजर डालें तो लगभग 80 प्रतिशत लोग मजदूर वर्ग में आते हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के मजदूर शामिल हैं। चाहे खेतों में काम करने वाला मजदूर हो, कारखानों में काम करने वाला हो या किसी अन्य क्षेत्र का श्रमिक, उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय दिखाई देती है।आज विकसित, विकासशील और गरीब सभी देशों में मजदूरों के सामने जीवन-मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है। भारत की स्थिति देखें तो जनसंख्या विस्फोट स्पष्ट दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है और चीन से लगभग 29 लाख अधिक होकर विश्व में प्रथम स्थान पर है। ऐसी स्थिति में सरकार और राजनीतिक नेताओं को मजदूरों की हर संभव सहायता करना अत्यंत आवश्यक है।देश में मुट्ठीभर राजनीतिक नेताओं के पास अरबों-खरबों रुपये की चल-अचल संपत्ति है। यदि इस संपत्ति का उपयोग मजदूरों के हित में किया जाए तो यह एक बड़ा सहारा साबित होगा। मजदूर को दुनिया का "शिल्पकार" कहा जाता है और किसान को "अन्नदाता"। दोनों की भूमिका देश और विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर, मस्जिद, कारखाने, सरकारी इमारतें, ताजमहल, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, कुतुब मीनार, संसद भवन, अयोध्या का राम मंदिर और बड़े-बड़े किले ये सभी मजदूरों की मेहनत से बने हैं।फिर भी आज इस "शिल्पकार" की हालत बेहद खराब है। मजदूर दुनिया का सबसे बड़ा आधार है मजदूर नहीं तो कुछ भी नहीं। यह बात भारत सहित पूरे विश्व को समझनी होगी। मजदूर वर्ग की समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि उनका जीवनयापन कठिन हो गया है। यदि भारत के EPS-95 के डेढ़ करोड़ पेंशनधारकों को देखें तो उन्हें मात्र 1000 से 3000 रुपये तक पेंशन मिल रही है, जिससे उनका गुजारा और इलाज संभव नहीं है।असंगठित मजदूरों की स्थिति और भी अधिक गंभीर है। महामारी (2019–2021) ने उनकी हालत को और खराब कर दिया। आज किसान पहले से ही संकट में है, लेकिन मजदूरों की स्थिति उससे भी अधिक चिंताजनक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और विशाल जनसंख्या वाला भी है। मजदूर अपनी मेहनत से देश के विकास में योगदान देता है, लेकिन उसे उसके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता।अब समय आ गया है कि समान कानून, समान अधिकार, समान संपत्ति, समान वेतन और समान पेंशन पर गंभीरता से विचार किया जाए। एक परिवार के पास रहने के लिए कितनी जगह और जीवनयापन के लिए कितनी संपत्ति होनी चाहिए, इस पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को विचार करना चाहिए।आज स्थिति यह है कि राजनीतिक नेता संपन्न हैं और मजदूर भूखा है। इसी कारण महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्याएं, महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। राजनीतिक नेता समानता की बात करते हैं, लेकिन यह केवल राजनीति तक सीमित रह जाती है।इसलिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सरकार को समान अधिकार और समान वेतन पर कानून बनाना चाहिए। तभी गरीब और मजदूर वर्ग को राहत मिलेगी, अन्यथा अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब और गरीब होता जाएगा।सरकार को मजदूरों के प्रति संवेदनशील होकर ठोस कदम उठाने चाहिए। EPS-95 पेंशनधारकों की मांग है कि उन्हें कम से कम 7500 रुपये पेंशन, महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। यदि सरकार यह मांग पूरी करती है तो मजदूरों को वास्तविक न्याय मिलेगा।सरकार को मजदूरों के घाव पर मरहम लगाने का कार्य करना चाहिए, तभी मजदूर दिवस सार्थक होगा। "जिस देश का मजदूर सुखी, वह देश सुखी" यह सत्य है। मजदूर आंदोलन कमजोर हो चुके हैं, इसलिए अब सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि वह मजदूरों के हित में निर्णय ले।मजदूरों की कार्यकुशलता का उचित मूल्य मिलना चाहिए, क्योंकि वही विश्व का आधार है। इस आधार को मजबूत बनाए रखना पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। सरकार और पूंजीपति वर्ग को मजदूरों के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना अपनानी चाहिए।मजदूर दिवस के अवसर पर यदि राजनीतिक नेता मजदूरों को न्याय देने का संकल्प लें, तभी इस दिन का महत्व सिद्ध होगा। साथ ही बदलते पर्यावरण को देखते हुए इस दिन बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर इसे मनाया जाए, जिससे प्रकृति भी सुरक्षित रहे।

लेखक सैयद इसरार हुसैन

पेपर लीक - लचर न्याय प्रक्रिया के साइड इफेक्ट

लेखक- डॉ योगेन्द्र श्रीवास्तव

एक बार फिर नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई। पिछले दस सालों में यह चौथा मौका है जब देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक नीट यूजी में पेपर लीक होने की घटना हुई है। नीट के अलावा पिछले दस सालों में लगभग सौ प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द की गई हैं। विश्वगुरु होने का दावा करने वाले देश के लिये यह बेहद शर्मनाक घटना है। प्रतियोगी परीक्षा के पीछे केवल परीक्षार्थियों की मेहनत और महत्वाकांक्षा ही ध्वस्त नहीं होती, उनके परिवार के सपने भी टूटते हैं और सारा त्याग और सम्बल व्यर्थ हो जाता है। साथ ही देश के संसाधनों की बरबादी होती है और छात्रों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। उन्नत टेक्नोलॉजी के दौर में देश एक सुरक्षित और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित नहीं कर पाता तो यह सिस्टम की घोर असफलता है। समय और संसाधनों की बरबादी के अलावा ऐसी घटनाओं से देश की प्रतिष्ठा हानि भी होती है। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे कई फैक्टर हैं जैसे छात्रों और उससे ज्यादा उनके परिवारों की महत्वाकांक्षा, गलाकाट प्रतिस्पर्धा, कोचिंग संस्थानों का रैकेट और काला धन। दरअसल पढ़ाई या नौकरी से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा शिक्षा व्यवस्था के दलालों और कोचिंग रैकेट के सरगनाओं के लिए एक कमाई का मौका बन जाती है। पेपर लीक तो सिर्फ पहली सीढ़ी है, उसके बाद मूल्यांकन में गड़बड़ी, मेरिट लिस्ट में हेराफेरी, अलॉटमेंट में जुगाड़ वगैरह सब पर शिक्षा माफिया का कंट्रोल होता है। अगर कहीं चूक हो जाए तो शोर मच जाता है वरना ये सब घोटाला बदस्तूर चलता रहता है।

लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है; हमारी लचर न्याय प्रक्रिया! समाज के हर क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध वास्तव में कमजोर न्याय प्रक्रिया का साइड इफेक्ट है। मसलन बीसियों बार पेपर लीक हो चुके हैं अथवा नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की गई है मगर हमारी सरकारें कुछ सीखती ही नहीं। लोगों को वर्ष 2013 में मध्यप्रदेश का बहुचर्चित और बदनाम व्यापम घोटाला जरूर याद होगा जिसमें अनेक अपात्रों को मेडीकल कॉलेजों में दाखिला और कई अन्य विभागों में नौकरी दिलाई गई थी। मगर यह किसी को याद नहीं होगा कि पुलिस की चार्ज शीट में लगभग 3000 लोगों के नाम होने के बाद बमुश्किल 100 लोगों को सजा हुई। वह भी लम्बी ट्रायल, जमानत और अपील वगैरह के बाद। ऐसा अमूमन हर घोटाले के साथ होता है। पकड़े जाने पर मीडिया में शोरगुल, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन, जाँच और फिर कानूनी प्रक्रिया का लम्बा दौर। कई बार तो आरोप पत्र ही सालों बाद कोर्ट में पेश होता है। इस लेट लतीफी का लाभ लेकर जमानत पर छूटे चतुर अपराधी सबूतों और गवाहों की भूल भुलैया में केस उलझा देते हैं। आखिर में कुछ लोगों को दण्डित कर मामला खत्म कर दिया जाता है। इस सारी प्रक्रिया में सिस्टम से जुड़े उच्चाधिकारी साफ बच निकलते हैं क्योंकि उनके अलिखित आदेशों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। ये तमाशा केवल पेपर लीक और परीक्षाओं के मैनेज करने तक नहीं बल्कि हर तरह के भ्रष्टाचार में दिखाई देता है। ईडी, इन्कम टैक्स, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जीएसटी वगैरह किसी भी एजेंसी का मामला हो आखिर में अंजाम लगभग यही होता है। डकैती, रेप और हत्या जैसे संगीन अपराधों में भी न्याय प्रक्रिया की कमजोरी और लेट लतीफी आखिर अपराधियों को ही लाभ पहुंचाती है।जनता भी जब-तब उजागर होने वाले नए घोटालों की सनसनी में पुराने मामले भूलती जाती है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलन्द हैं कि आजकल जमानत पर छूटने का भी जश्न मनाया जाता है। जाहिर है कि जमानत पर छूट जाना ही अपराधी के लिए कामयाब हो जाना है क्योंकि मुकदमा तो सालों तक चलना निश्चित ही है। कई अपराधी जमानत पर छूटकर दोबारा भी अपराध कर गुजरते हैं। अधिकांश घोटाले अथवा अपराध कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं लेकिन जब पेपर लीक या नियुक्ति रद्द होने जैसी घटनाएं होती हैं तो लाखों लोग प्रभावित होते हैं। नीट यूजी की परीक्षा लगभग 22 लाख छात्रों ने महीनों की कड़ी मेहनत झोंक दी होगी। वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में लगभग 25000 नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था। हाल में ही मध्यप्रदेश में 13000 प्राथमिक शिक्षकों की चयन सूची पर रोक लगा दी गई है। परीक्षा एवं चयन में गड़बड़ी के ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब परीक्षार्थियों अथवा प्रतिस्पर्धियों की मेहनत व्यर्थ गई और उनके सपने टूट गए।स्पष्ट है कि अपराधियों, आला अफसरों और राजनेताओं की मिलीभगत के बिना ऐसा होना सम्भव ही नहीं।

खेदजनक तथ्य यह है कि राजनीति और अपराध के गठजोड़ के चलते कानून का डर धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। एक आम आदमी जरूर कानून से डरता है लेकिन अपराधी बेखौफ अपराध करते रहते हैं क्योंकि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। रेत माफिया और जंगल माफिया के पुलिस और अधिकारियों पर हमले उनकी राजनेताओं से सांठ गांठ के उदाहरण हैं। यह समझना मुश्किल नहीं कि अपराधी और राजनेता अब एक दूसरे के हितसाधक हो गए हैं। इससे ज्यादा त्रासद और शर्मनाक क्या होगा कि आपराधिक मामलों में लिप्त सैकड़ों राजनेता विधायक और सांसद बने हुए हैं। न्याय प्रक्रिया की लापरवाही और लेट लतीफी के चलते ऐसे राजनेता कानून के उस सिद्धान्त का सहारा लेते हैं कि; दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष है। बहुतों को आखिरकार सजा होती भी है लेकिन तब तक वे कई महत्वपूर्ण पद सुशोभित कर चुके होते हैं। अपराधियों में कानून का भय खत्म हो जाना समाज के लिए खतरे की घंटी है और इसके परिणाम दिखाई भी देने लगे हैं। अगर समय रहते न्याय प्रक्रिया में व्यापक और वांछित सुधार नहीं किए गए तो यह अनदेखी समाज और देश के लिए बहुत घातक साबित होगी।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

कोहली ने पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान समेत 4 बैटर का यह रिकॉर्ड तोड़ा

ध्वस्त किया गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड

नई दिल्ली। विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के 57वें मैच में केकेआर के खिलाफ गजब की पारी खेली और शतक (नाबाद 105 रन) लगाया।

केकेआर के खिलाफ पहले दो मैचों में डक पर आउट होने वाले कोहली ने क्या गजब की वापसी की और अपने आईपीएल करियर का 9वां शतक लगा दिया। यही नहीं ये कोहली को टी20 क्रिकेट करियर का 10वां शतक भी रहा। कोहली ने इस शतकीय पारी के दम पर पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान समेत 4 बैटर्स का यह रिकॉर्ड तोड़ा जबकि क्रिस गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया।

टी20 क्रिकेट में 14,000 रन भी पूरे किए

कोहली ने केकेआर के खिलाफ अपनी नाबाद 105 रन की पारी के दौरान टी20 क्रिकेट में 14,000 रन भी पूरे किए। वो अब टी20 प्रारूप में सबसे कम पारियों में 14 हजार रन बनाने वाले बैटर बने। उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गेल ने ये कमाल 423 पारियों में किया था जबकि कोहली ने ऐसा सिर्फ 409 पारियों में किया।

कोहली ने डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली जिन्होंने टी20 में 10 शतक लगाए थे

कोहली ने केकेआर के खिलाफ जो शतक लगाया ये उनके टी20 करियर का 10वां शतक रहा। उन्होंने साहिबजादा फरहान, अभिषेक शर्मा, क्विंटन डिकॉक और रिली रोसो को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने टी20 क्रिकेट में अब तक 9-9 शतक लगाए हैं। कोहली ने डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली जिन्होंने टी20 में 10 शतक लगाए थे और इस प्रारूप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वॉर्नर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ गए।

सबसे कम पारियों में 14 हजार रन

- 409 पारी - विराट कोहली
- 431 पारी - डेविड वॉर्नर
- 505 पारी - एलेक्स हेल्स
- 423 पारी - क्रिस गेल
- 468 पारी - जोस बटलर
- 633 पारी - कीरोन पोलार्ड

कोहली ने रोहित की कर ली बराबरी

केकेआर के खिलाफ नाबाद 105 रन की पारी खेलने वाले कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल में ये उनका 21वां प्लेयर ऑफ द मैच खिताब रहा और उन्होंने रोहित शर्मा की बराबरी कर ली। इस लीग में वो अब रोहित के साथ सबसे ज्यादा बार ये खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। दूसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं।

सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच खिताब जीतने वाले भारतीय

21 - विराट कोहली
21 - रोहित शर्मा
18 - एमएस धोनी
17 - रवींद्र जडेजा
17 - केएल राहुल
16 - यूसुफ पठान

आईपीएल में 9वें शतक के साथ विराट कोहली ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

आईपीएल 2026 के 57वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को 6 विकेट से हराया। आरसीबी की इस जीत के नायक विराट कोहली रहे, जिन्होंने 105 रनों की नाबाद पारी खेली। कोहली ने अपनी इस शतकीय पारी के साथ रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई। कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों की अपनी पारी में 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 11 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 92 रनों की अहम साझेदारी निभाई। आईपीएल में यह कोहली का 9वां शतक है। विराट ने केकेआर के खिलाफ यह आईपीएल में दूसरा शतक लगाया।

कोहली ने इस लीग में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में जोस बटलर की बराबरी कर ली है। बटलर ने केकेआर और आरसीबी के खिलाफ दो-दो शतक लगाए हैं। आईपीएल में रनों का पीछा करते हुए विराट कोहली संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। चेज करते हुए विराट ने यह तीसरा शतक लगाया। कोहली के अलावा यह कारनामा सिर्फ जोस बटलर ही कर सके हैं। विराट टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। कोहली के बल्ले से टी20 क्रिकेट में यह 10वां शतक निकला। विराट आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं।

इटैलियन ओपन

कोको गॉफ ने मिरा एंड्रीवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

रोम। अमेरिका की कोको गॉफ ने रूस की मिरा एंड्रीवा को हराकर इटैलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुनिया की नंबर 3 खिलाड़ी कोको गॉफ को नंबर 8 सीड एंड्रीवा के खिलाफ तीसरे सेट में लगभग 5-1, दो-ब्रेक की बढ़त के साथ, 4-6, 0-2, 6-4 से जीत हासिल करने के लिए पांच मैच पॉइंट्स की जरूरत पड़ी। एंड्रीवा ने पहले सेट में 3-1 की बढ़त बनाई और कई बार इसे अच्छे से संभाला। डब्ल्यूटीए की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले सेट में, एंड्रीवा ने 10 विनर और सिर्फ सात अनफोर्स्ड एरर के साथ खत्म किया, और गॉफ के लिए इसका उल्टा हुआ। गॉफ ने 3-0 की बढ़त बनाई, एक ब्रेक लिया, और दूसरे सेट में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एंड्रीवा ने दूसरे सेट में 11 अनफोर्स्ड एरर किए, जिससे गॉफ ने डिसाइडर सेट के लिए मजबूर कर दिया। शुरू में ऐसा लगा कि गॉफ 5-1 की बढ़त के साथ डबल ब्रेक लेकर जीत जाएंगी। गॉफ ने दूसरे सेट से ही मोमेंटम बनाए रखा था और एंड्रीवा की गलतियों का फायदा उठाया। कोको गॉफ का सेमीफाइनल मुकाबला सोराना सिर्स्टिया से होगा। इस सीजन में गॉफ का रोमानियाई सिर्स्टिया से तीसरा मुकाबला लगातार दूसरे टूर्नामेंट में होगा। अमेरिकी खिलाड़ी अपने 15वें 1000-लेवल डब्ल्यूटीए टूर सेमीफाइनल में पहुंची हैं। वहीं, 2026 में दुबई और मियामी ओपन के बाद तीसरे सेमीफाइनल में गॉफ ने जगह बनाई है। ओपन एरा में नथाली तौजियात (1989) के बाद इटैलियन ओपन में पहुंचने के लिए तीन या उससे ज्यादा कमबैक जीत हासिल करने वाली वह सिर्फ दूसरी खिलाड़ी हैं। कोको गॉफ ने पिछले सीजन में भी इटैलियन ओपन का फाइनल खेला था। गॉफ को हार का सामना करना पड़ा था। जैस्मीन पाओलिनी ने फाइनल में कोको गॉफ को 6-4, 6-2 से हराकर खिताब जीता था।

व्यापार

नई थम रही रुपये की गिरावट, डॉलर के मुकाबले फिर पहुंचा ऑल टाइम लो पर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रुपये में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रुपया आज शुरुआती कारोबार में 20 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 95.86 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया संकट को लेकर चिंताओं से रुपये पर भारी दबाव है। रुपया इस साल एशिया की सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है और इसमें अब तक छह प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ चुकी है। महंगा कच्चा तेल, मजबूत अमेरिकी डॉलर और पश्चिम एशिया संकट को लेकर बढ़ती चिंताएं इसकी मुख्य वजह हैं।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.74 प्रति डॉलर पर खुला। फिर टूटकर 95.86 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 20 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 95.80 पर पहुंचने के बाद 95.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। रुपये की गिरावट को थामने के लिए आरबीआई अब तक अरबों डॉलर झोंक चुका है। जानकारों का कहना है कि अगर केंद्रीय बैंक ऐसा नहीं करता तो रुपये की हालत और बदतर होती। लगातार तीसरे दिन डॉलर के मुकाबले रेकॉर्ड लो पर पहुंचा रुपया भारत का करीब 90% कच्चा तेल और 50% गैस बाहर से आती है ईरान युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमत में 50 फीसदी तेजी आई है साथ ही विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में बिकवाली जारी है इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.48 पर रहा। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.44 प्रतिशत की बढ़त के साथ 106.10 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को शुद्ध बिकवाल रहे थे और उन्होंने 4,703.15 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। डॉलर के मुकाबले रुपये में इस हफ्ते 1.4% गिरावट आई है। पिछले तीन दिन इसने हर सेशन में ऑल टाइम लो छुआ है। भारत का करीब 90 फीसदी कच्चा तेल और 50 फीसदी गैस बाहर से आती है। लेकिन ईरान युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमत में 50 फीसदी तेजी आई है।

चलते-चलते रास्ते में दो समझौते और दूर हो जाएगी एलपीजी की किल्लत!

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई को चार यूरोपीय देशों की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वह कुछ घंटे के लिए खाड़ी देश यूएई में भी रुकेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच दो अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ये एलपीजी और स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़े हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि मोदी के यूएई में तीन घंटे के स्टॉपओवर के दौरान एनर्जी सिक्योरिटी सबसे अहम मुद्दा होगा। ईरान युद्ध के कारण दुनिया में एनर्जी की सप्लाई टाइट हो गई है। भारत पर भी इसका असर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री ने हाल में लोगों से पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील की थी। यूएई भारत का अहम एनर्जी सप्लायर है। यह भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा बड़ा सोर्स होने के साथ-साथ एलपीजी और एलएनजी का दूसरा बड़ा सप्लायर है। ईरान युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही बंद है।

इस कारण अप्रैल में खाड़ी देशों के उत्पादन में गिरावट आई है। अप्रैल में केवल यूएई के उत्पादन में तेजी आई। इसकी वजह यह है कि वह होर्मुज स्ट्रेट को बाइपास करके गल्फ ऑफ ओमान में स्थित फुजैरा पोर्ट से तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। मोदी 15 मई को चार यूरोपीय देशों की की यात्रा पर रवाना होंगे इस दौरान वह करीब तीन घंटे के लिए खाड़ी देश यूएई में रुकेंगे इस दौरान एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े दो समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे ईरान युद्ध के कारण दुनिया में एनर्जी की सप्लाई टाइट हो गई है यूएई रोजाना करीब 3.6 मिलियन बैरल तेल उत्पादन कर रहा है

20 फीसदी कच्चा तेल इसी रास्ते गुजरता है। कच्चा तेल महंगा होने से भारत की इकॉनमी पर भी असर दिखने लगा है क्योंकि हमारा करीब 90 फीसदी तेल बाहर से आता है। ऐसे में यूएई के साथ समझौते भारत के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं।

उत्पादन बढ़ाने की तैयारी

यूएई रोजाना 3.2 से 3.6 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन कर रहा है। हाल में वह ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर आ चुका है और अगले साल तक रोजाना 5 मिलियन बैरल तेल निकालने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यूएई काफी अहम है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि मोदी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ आपसी रिश्तों, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत की यूएई के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। 45 लाख से अधिक भारतीय इस खाड़ी देश में रहते हैं।

ईरान युद्ध का असर

पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई को ढाई महीने हो चुके हैं और फिलहाल इसके थमने की उम्मीद नहीं है। इसके कारण होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से कच्चे तेल की सप्लाई टाइट हुई है।

रूसी तेल खरीद पर पाबंदियों में मिली छूट होने वाली है खत्म

अमेरिका के सस्पेंस से भारत की बढ़ी टेंशन

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत की नजर 16 मई पर टिकी हुई है। इस हफ्ते के आखिर तक अमेरिका की पाबंदियों में मिली छूट को अगर आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो भारतीय तेल रिफाइनरों के लिए मुश्किल पैदा होगी। उन्हें रूसी कच्चे तेल का आयात कम करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। वहीं, स्थानीय प्रोसेसर ईरान युद्ध के नतीजों से जूझ रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने भारतीय रिफाइनरों के रुख से परिचित लोगों के हवाले से बताया, अमेरिका ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि क्या वह उस छूट को आगे बढ़ाएगा, जिससे भारत सहित अन्य देश 16 मई के बाद भी तेल खरीदना जारी रख सकें। रिपोर्ट के अनुसार, अगर ऐसा नहीं होता है तो स्थानीय प्रोसेसरों को कहीं और से ज्यादा कीमत वाले और वैकल्पिक 'स्पॉट बैरल' (बाजार में तुरंत उपलब्ध तेल) खरीदने पर मजबूर होना पड़ सकता है। मई महीने में अब तक रूसी तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर यानी 23 लाख बैरल प्रतिदिन रहा है। ऐसा

इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका से मिली छूट के तहत पहले से ही जहाजों में लदे रूसी तेल के आयात की अनुमति थी। लेकिन, मॉस्को से कच्चा तेल लेकर अगर कोई नया जहाज भारत की ओर आता हुआ नहीं दिखता है तो स्थिति बदलेगी। उस स्थिति में पूरे महीने का कुल आयात घटकर 19 लाख बैरल प्रतिदिन तक गिर सकता है। ईरान युद्ध के कारण तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मची हुई है। इस युद्ध ने फारस की खाड़ी से भारत सहित अन्य प्रमुख खरीदारों तक होने वाली तेल की बड़ी सप्लाई को बाधित कर दिया है। भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के प्रयासों के तहत अमेरिका ने सबसे पहले 5 मार्च को भारत के लिए एक विशेष छूट जारी की थी। इसके तहत भारतीय रिफाइनरों को जहाजों में लदे रूसी तेल को खरीदने की अनुमति दी गई थी। एक बार विस्तार मिलने के बाद अब यह छूट 16 मई को समाप्त होने वाली है। इस समय-सीमा के समाप्त होने से ठीक पहले भारत की दो सबसे बड़ी सरकारी तेल रिफाइनिंग कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने इस हफ्ते पश्चिम अफ्रीका और अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद की है।

फेंके हुए जूतों से झुग्गी बस्ती में शुरू किया काम, अब 3 करोड़ का बिजनेस, हर कोई हैरान

नई दिल्ली, एजेंसी। श्रीयांश भंडारी और रमेश धामी मुंबई के रहने वाले हैं। दोनों ही एथलीट रहे हैं। इन्होंने एक सफल स्टार्टअप खड़ा कर दिया है। इसका नाम 'ग्रीनसोल' है। दोनों ने इसकी नींव 2015 में रखी थी। यह पुराने और फेंके हुए जूतों को रिसाइकिल करके चप्पलें बनाता है। इसकी शुरुआत झुग्गी-बस्ती से हुई थी। यह पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण को एक साथ जोड़ता है। एक ओर जहां यह स्टार्टअप सालाना 3 करोड़ रुपये की कमाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसने पर्यावरण में कचरा कम करने में मदद की है। आइए, यहां श्रीयांश भंडारी और रमेश धामी की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं।

ऐसे आया आइडिया

इस सफर की शुरुआत तब हुई जब एथलीट श्रीयांश भंडारी ने अपने साथी और मैराथन कोच रमेश धामी को पुराने जूतों की मरम्मत करते देखा। रमेश अपने उन जूतों को फेंकना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका 'सोल' अभी भी मजबूत था। इस साधारण सी घटना ने उन्हें गहरी रिसर्च के लिए प्रेरित किया। तब उन्हें पता चला कि दुनिया भर में अरबों जूते लैंडफिल में फेंक दिए जाते हैं। इन्हें नष्ट होने में 200 साल से अधिक समय लगता है। इसी समस्या को समाधान में बदलने के लिए दोनों ने मिलकर अपने स्टार्टअप की नींव रखी।

झुग्गी बस्ती में शुरुआत

शुरुआती सफर काफी चुनौतीपूर्ण था। दोनों संस्थापकों का फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग से कोई वास्ता नहीं था। मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में किराए की छोटी सी यूनिट से उन्होंने अपने काम की शुरुआत की। वे दिन में सिर्फ 15-20 जोड़ी जूते ही बना पाते थे। लेकिन 'राम फैशन एक्सपोर्ट्स' के साथ पार्टनरशिप ने उनके लिए गेम-चेंजर का काम किया। उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिसमें पुराने जूतों को काटकर स्टैंडर्ड साइज दिया जाता है। उसमें 20% नया मटेरियल जोड़कर उसे स्वच्छ और आरामदायक बनाया जाता है।

20 राज्यों में फैला नेटवर्क

श्रीयांस और रमेश का स्टार्टअप हर महीने 15,000 से 20,000 जोड़ी पुराने जूते जुटाता है। इन जूतों को पूरी तरह से खोलकर उनके हिस्सों को अलग किया जाता है। फिर बच्चों के साइज के हिसाब से 'डाई-कटिंग' की जाती है। ग्राउंड टीम गांवों और आदिवासी इलाकों में जाकर बच्चों के पैरों का माप लेती है ताकि उन्हें सही फिटिंग की चप्पलें मिल सकें। 100 से अधिक कॉर्पोरेट पार्टनर्स के सीएसआर सहयोग से यह नेटवर्क आज भारत के 20 राज्यों तक फैल चुका है।

बड़ा है आगे का टारगेट

चैरिटी के अलावा स्टार्टअप का एक रिटेल ब्रांड भी है जो इको-फ्रेंडली स्नीकर्स और एक्सेसरीज बेचकर सालाना 2.5 से 3 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल कर रहा है। यह मॉडल न केवल कचरे को कम करता है बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। भविष्य में श्रीयांश और रमेश का टारगेट इस मॉडल को नेपाल, भूटान और अफ्रीका जैसे देशों में ले जाना है। साथ ही, वे जूते के कचरे का इस्तेमाल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रनिंग ट्रैक बनाने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने की योजना बना रहे हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)